RIN No.: MPBIL/2001/5256
DAVP Code : 128101
Postal Registration No. : भोपाल/म.प्र./581/2021-2023
Publish Date : Every Month Dt. 05
Posting Date : Every Month Dt. 15
Rs. 10/-

मध्यप्रदेश/छत्तीसगढ़

वर्ष 23 अंक 01 05 सितम्बर 2022

जगत विज़न

राजनीतिक साजिशों और गैर कानूनी गतिविधियों का

नया अड्डा बना छत्तीसगढ़

झारखण्ड के विधायकों को बघेल ने कराई अय्याशी !

प्रेरणा स्त्रोत : स्व. श्री जगत पाठक

संपादक	विजया पाठक
कार्यकारी संपादक	समता पाठक
मध्यप्रदेश संवाददाता	अर्चना शर्मा
राजनीतिक संवाददाता	समीर शास्त्री
विशेष संवाददाता	बिन्देश्वरी पटेल
छत्तीसगढ़ ब्यूरो चीफ	मणिशंकर पाण्डेय
छत्तीसगढ़ संवाददाता	आनन्द मोहन श्रीवास्तव,
पश्चिम बंगाल ब्यूरो चीफ	अमित राय
गोवा ब्यूरो चीफ	अजय सिंह
गुजरात ब्यूरो चीफ	गौरव सेठी
दिल्ली ब्यूरो चीफ	विजय वर्मा
पटना संवाददाता	सौरभ कुमार
उत्तरप्रदेश ब्यूरो चीफ	वेद कुमार
बुंदेलखण्ड संवाददाता	रफत खान
विधिक सलाहकार	एडवोकेट राजेश कुंसारिया

सम्पादकीय एवं विज्ञापन कार्यालय

भोपाल

एफ-116/17, शिवाजी नगर, भोपाल
मो. 98260-64596, मो. 9893014600
फोन : 0755-4299165 म.प्र. स्वत्वाधिकारी,

छत्तीसगढ़

4-विनायका विहार, रिंग रोड, रायपुर

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक,
विजया पाठक द्वारा समता ग्राफिक्स एफ-116/17, शिवाजी नगर, भोपाल म.प्र. द्वारा कम्पोज एवं जगत प्रिंटर्स एण्ड पब्लिशर्स प्लाट नं. 28 सुरभि विहार बीडीए रोड भेल भोपाल से मुद्रित एवं एफ-116/17, शिवाजी नगर, भोपाल म.प्र. से प्रकाशित संपादक विजया पाठक। समस्त विवादों का कार्यक्षेत्र भोपाल सत्र-न्यायालय रहेगा। पत्रिका में प्रकाशित किये जाने वाले संपूर्ण आलेख एवं सामग्री की जिम्मेदारी लेखक एवं संपादक की होगी।

E-mail : jagat.vision@gmail.com
Website: www.jagatvision.in

मासिक द्विभाषी पत्रिका वर्ष 23 अंक 01 05 सितम्बर 2022

राजनीतिक साजिशों और गैर कानूनी गतिविधियों का

नया अड्डा बना छत्तीसगढ़

झारखण्ड के विधायकों को बघेल ने कराई अय्याशी!

(पृष्ठ क्र.-6)

■ क्या बीजेपी के निशाने पर है दिल्ली सरकार 30

■ नीतिश के बने रहने की होगी चुनौती 34

■ चुनावों से पहले यह है भाजपा का बड़ा मास्टर स्ट्रोक 40

■ जब कटनी के हर घर और दुकान में लहराया थ तिरंगा 44

■ जल जीवन मिशन में 26 माह में पहुंचा 52 लाख घरों में जल 46

■ प्रदेश में बारिश, बाढ़ और बदइंतजामी 48

■ Extreme Poverty and the application of Microfinance 60

कलम के गुनहगार
PRESS

मोदी सरकार के खिलाफ कांग्रेस का हल्लाबोल

दिल्ली के रामलीला मैदान में महंगाई के खिलाफ कांग्रेस ने हल्लाबोल रैली की। इस रैली में देशभर से कांग्रेस कार्यकर्ता पहुंचे। कांग्रेस की भ्रष्टाचार और महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल रैली में पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी सहित 17 नेताओं ने सभा को संबोधित किया और सभी ने गांधी के नेतृत्व की तरीफ करते हुए मोदी सरकार पर तीखे प्रहार किये। इस रैली में कांग्रेस की एकता का आभाष हुआ। सभी बड़े नेताओं ने एक बार फिर गांधी परिवार की नेतृत्व श्रमता पर विश्वास किया। नफरत से लोग बंटते हैं, देश बंटता है, देश कमजोर होता है। बीजेपी-संघ के नेता देश को बांटते हैं, जानबूझकर देश में भय पैदा करते हैं, नफरत पैदा करते हैं। हिंदुस्तान में डर बढ़ता जा रहा है। किस चीज का डर, भविष्य का डर, महंगाई का डर, बेरोजगारी का डर। ये डर बढ़ता जा रहा है, इसके कारण हिंदुस्तान में नफरत बढ़ती जा रही है। दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस की महंगाई पर हल्ला बोल रैली के दौरान पार्टी नेता राहुल गांधी ने ये बातें कहीं। राहुल गांधी 7 सितंबर से भारत जोड़ो यात्रा शुरू करने से पहले दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में महंगाई और बेरोजगारी के मामले में मोदी सरकार पर हमलावर थे लेकिन इसे 2024 के चुनाव से पहले कांग्रेस की तैयारी की शुरुआत के तौर पर भी देखा जा रहा है। उन्होंने कहा, आप चले जाइए आज किसी भी दुकानदार, मज़दूर और किसान से पूछ लीजिए कि यूपीए और आज के समय में क्या अंतर है। यूपीए के सरकार में 70 हज़ार करोड़ रुपये किसानों को दिए। नरेंद्र मोदी जी ने तीन काले क़ानून दिए। मज़दूरों के लिए यूपीए मनरेगा दिया। मोदी जी ने संसद में मनरेगा को लिए बोला ये बेकार है। आज उन्हें मनरेगा देना पड़ रहा है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर कड़ा हमला करते हुए कहा है कि पिछले आठ साल में बेरोजगारी तथा महंगाई चरम पर पहुंची है और सरकार ने इसे रोकने के प्रयास करने की बजाए जन विरोधी कदम उठाकर भय और नफरत फैलाने का काम किया है। देश के हालात आज बहुत खराब हो गये हैं। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तब से देश में नफरत और क्रोध बढ़ता जा रहा है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के आने बाद नफरत लगातार फैल रही है लेकिन सरकार उसे रोक नहीं रही है। इसी तरह से देश में डर का माहौल है और यह लागातार बढ़ता ही जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस सरकार के आने क बाद से एक नहीं कई डर पैदा हुए हैं। सरकार की गलत नीतियों के कारण लोगों में अपने भविष्य का डर है, महंगाई का डर है और बेरोजगारी का डर है। कांग्रेस नेता ने कहा, मुश्किल यह है कि यह डर कम नहीं हो रहा है, ये डर बढ़ता जा रहा है, इसके कारण हिंदुस्तान में नफरत बढ़ती जा रही है। नफरत से लोग बंटते हैं, देश बंटता है, देश कमजोर होता है। उन्होंने कहा, आज महंगाई और बेरोजगारी ने देश में सबसे ज्यादा मुश्किल पैदा कर दी है। देश जिन मुश्किलों से गुजर रहा है इसका पूरा श्रेय भाजपा की गैर-जिम्मेदार सरकार को जाता है। आज देश अगर चाहे भी तो अपने युवाओं को रोजगार नहीं दे पाएगा। आपको आज जो बेरोजगारी दिख रही है, वो आने वाले समय में और बढ़ेगी।

गौरतलब है कि कांग्रेस 07 सितंबर से कश्मीर से कन्याकुमारी तक की 3500 किलोमीटर की भारत जोड़ो यात्रा शुरू कर रही है। राहुल गांधी इस पूरी यात्रा के दौरान महंगाई, बेरोजगारी का मुद्दा उठाएंगे और सांप्रदायिक सदभाव को बढ़ाने की अपील करेंगे। राहुल ने भले ही इस रैली में मोदी राज में महंगाई, बेरोजगारी और सांप्रदायिकता बढ़ने के खतरे का मुद्दा उठाया लेकिन उन्होंने गुजरात, हिमाचल के विधानसभा चुनावों से लेकर 2024 में मोदी सरकार के खिलाफ लोकसभा चुनाव की तैयारियों के भी संकेत दे दिए। इसमें विपक्षी एकता की अपील भी दिख रही थी। कांग्रेस की सक्रियता देखने से लगता है कि 2024 के चुनाव से पहले उसने अपनी पूरी ताकत बटोरने की कोशिश शुरू कर दी है। 2022 के आखिर में गुजरात और हिमाचल में चुनाव हो सकते हैं। 2023 में नौ राज्यों के विधानसभा चुनाव और 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं। लिहाजा कांग्रेस ने अभी से खुद को मजबूत करने की कोशिश नहीं की तो 2024 के चुनाव में विपक्ष तो दूर यूपीए का नेतृत्व करने में भी उसे चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। अक्टूबर महीने में कांग्रेस अध्यक्ष का भी चुनाव होना है। अगर राहुल अध्यक्ष बनते हैं तो उन्हें आक्रामक नेतृत्वकारी की भूमिका में दिखना होगा। उस हिसाब से इस तरह की रैलियां और यात्राएं कांग्रेस के लिए कारगर साबित हो सकती हैं।

विजया पाठक

राजनीतिक साजिशों और गैर कानूनी गतिविधियों का

नया अड्डा बना छत्तीसगढ़

झारखण्ड के विधायकों को बघेल ने कराई अय्याशी!

छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव में अब केवल लगभग एक साल का समय बचा है। इस शेष एक साल में प्रदेश की भूपेश सरकार लूट, खसोट और भ्रष्टाचार से अपनी तिजोरियों को भरने में लग गई है। क्योंकि सरकार के मुखिया और सिपहसलाहकारों को लगने लगा है कि आने वाले चुनाव में उन्हें सत्ता से बाहर होना पड़ेगा। यही कारण है कि सरकार सुशासन को छोड़ कुशासन की ओर बढ़ने में लग गई है। चारों ओर भ्रष्टाचार, अराजकता और भय का आतंक फैलाया जा रहा है। विधायक से लेकर मुख्यमंत्री तक तिजोरियों को भरने में लगे हैं। सरकार की इन कारगुजारियों को मीडिया में उजागर करने पर सख्त पाबंदी लगाई जा रही हैं। कोई मीडियाकर्मी या मीडिया संस्थान उजागर करता भी है तो उसे कई प्रकार से प्रताड़ित किया जाता है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ देश में राजनीतिक साजिशों और गैर कानूनी गतिविधियों का नया अड्डा बन गया है। यहां बड़े पैमाने पर इकट्ठा होने वाली ब्लैकमनी का बंटवारा राजनेताओं से लेकर माफियाओं तक होता है। इसमें प्रभावशील अफसरों खासकर आइएएस, आइएफएस अधिकारियों की हिस्सेदारी भी तय होती है। लिहाजा राजनेताओं के गोरखधंधों का नया ठिकाना राजधानी रायपुर बन गया है। ताजा मामला झारखण्ड की हेमंत सरकार पर लटकती बर्खास्तगी की तलवार से जुड़ा था। इस बीच सरकार बचाने की लगातार कोशिशें की जा रही थी। इस दौरान छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार और प्रदेश की शराबलॉबी ने हेमंत सोरेन से सरकार को बचाने के लिए लामबंदी की। झारखंड के विधायकों को रायपुर में रूकवाया गया। यहां भूपेश सरकार ने इन विधायकों की खूब आवभगत की। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल और उनके इर्द-गिर्द घूमने वाली चंडाल चौकड़ी में हाहाकार मचाया हुआ है। हम कह सकते हैं कि भूपेश बघेल सरकार को चार लोग मिलाकर चला रहे हैं। इस चांडाल चौकड़ी में दो पत्रकार विनोद वर्मा, रुचिर गर्ग एक प्रमोटी आईएएस अफसर अनिल टुटेजा और मुख्यमंत्री बघेल की खास सौम्या चौरसिया है। यह पूरी चौकड़ी मिलकर सरकार के हर फैसले में दखलअंदाजी करती है। छत्तीसगढ़ अराजकता के साथ-साथ अपराध का गढ़ भी बनता जा रहा है। प्रदेश में आपराधिक घटनाएं बढ़ती जा रहीं हैं। इन सबके पीछे भूपेश सरकार की कानून व्यवस्था का नाकामी नजर आ रही है। पत्रकारों पर अत्याचार चरम पर है। उन्हें अपनी मर्जी से लिखने या बोलने की आजादी छीन ली गई है। यदि पत्रकार अपनी बातें करता भी है तो उसे कई तरह से प्रताड़ित किया जाता है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि राज्य में भूपेश सरकार हर मोर्चे पर विफल है।

विजया पाठक

छत्तीसगढ़ देश में राजनीतिक साजिशों और गैर कानूनी गतिविधियों का नया अड्डा बन गया है। यहां बड़े पैमाने पर इकट्ठा होने वाली ब्लैक मनी का बंटवारा राजनेताओं से लेकर माफियाओं तक होता है। इसमें प्रभावशील अफसरों खासकर आइएएस, आइएफएस अधिकारियों की हिस्सेदारी भी तय होती है। लिहाजा राजनेताओं के गोरखधंधों का नया ठिकाना राजधानी रायपुर बन गया है। ताजा मामला झारखण्ड की हेमंत सरकार पर लटकती बर्खास्तगी की तलवार से जुड़ा था। भारत निर्वाचन आयोग ने हेमंत सोरेन की विधानसभा रद्द करने की सिफारिश 25 अगस्त 2022 को राजभवन भेज दी। बावजूद इसके कानूनी राय के मामले को राजभवन ने हफते भर के ज्यादा वक्त तक लटका दिया। राज्य में मुख्यमंत्री की बर्खास्तगी की खबरों के बीच अस्थिरता की स्थिति निर्मित हो गई। नतीजतन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को हाऊस ट्रेडिंग की अंदेशे के साथ पलायन को मजबूर होना पडा। पहले तो उन्होंने रांची के आसपास ही यूपीए विधायकों की बाड़ेबंदी की। लेकिन विधायकों के भाग निकलने के मद्देनजर उन्होंने छत्तीसगढ़ के रायपुर का रूख किया। बताया जाता है कि सीएम हेमंत सोरेन अपने विधायकों को लेकर कोलकाता रवाना हो रहे थे। इस बीच सरकार बचाने की लगातार कोशिशे की जा

छत्तीसगढ़ को बर्बाद और तोड़ने वाले भूपेश बघेल को मिला है भारत को जोड़ने का जिम्मा

राष्ट्रीय पत्रकारों से ऑन स्क्रीन झूठ बोलते हैं भूपेश बघेल

कहते हैं ना कि झूठ इतनी बार बोलो कि वो सच दिखने लगे। इसी थ्योरी पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल चल रहे हैं। छत्तीसगढ़ में जो अत्याचार, भ्रष्टाचार और आतंक की सरकार उनकी सरपरस्ती में ही चल रही है। चाहे ईडी की रेड होनी सीबीआई की सबमें वो अपने और अपने खास लोगों को टारगेट बताने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते हैं। अब तो भूपेश बघेल झूठ भी इतनी सफाई से बोलते हैं। शायद इसी भरोसे में कांग्रेस आलाकमान उनका प्रमोशन पे प्रमोशन कर रही है वो भी असलियत से परे होकर। इसका ताजा उदाहरण भूपेश बघेल द्वारा 02 सितंबर को दिये गये यू-ट्यूब पत्रकार समदीष के कार्यक्रम अनफल्टर्ड बाय समदीष में बोला। इस कार्यक्रम में जब समदीष ने आदिवासियों की जमीन को लेकर प्रश्न किया तो उत्तर में भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में आदिवासियों की जमीन नहीं ली जाती। जबकि सच परसा कॉल खदान में सबके सामने है। आदिवासियों का छत्तीसगढ़ में सरकार के खिलाफ आंदोलन भूपेश बघेल का झूठ उजागर करता है। एक प्रश्न पत्रकारों के खिलाफ कार्यवाही को लेकर पूछा तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसमें भी कोरा झूठ बोला। भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में किसी पत्रकार पर कार्यवाही सरकार के खिलाफ लिखने पे नहीं होता, वे यहीं नहीं रुके और कहा कि पत्रकार तो उनके मित्र हैं और वो जाकर जनसंपर्क विभाग में पूछे। अब दिल्ली से आए पत्रकार को क्या पता कि इनके खिलाफ लिखने से एक पत्रकार को लंबी जेल हुई, थाने में सैनिटाइजर पिलाया गया और तो और उनका घर भी जमींदोश कर दिया गया। एक पत्रकार को कार्टून बनाने के जुर्म में केस दर्ज हुआ। यहां तक मेरे खिलाफ भी अपराध पंजीबद्ध हुए और आगे भी इसी तैयारी में है। ऐसे काम से कम दर्जनों किस्से हैं। डर का वातावरण सरकार द्वारा पत्रकारों के बीच ऐसा बिठा दिया गया है जिससे छत्तीसगढ़ के पत्रकारों के भूपेश और उनकी चांडाल चौकड़ी के खिलाफ कुछ भी लिखने की हिम्मत नहीं बची है। पूरे कार्यक्रम में सिर्फ भूपेश बघेल द्वारा सिर्फ झूठ ही परोसा गया है।

रही थी। इस दौरान छत्तीसगढ़ की शराबलॉबी ने हेमंत सोरेन से सरकार को बचाने के लिए लामबंदी की। जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर मंडराते खतरे के बीच सोरेन को एक नई समस्या ने भी जकड़ा हुआ है। दरअसल आफिस

राजनेताओं के गोरखधंधों का नया ठिकाना राजधानी रायपुर बन गया है। ताजा मामला झारखण्ड की हेमंत सरकार पर लटकती बर्खास्तगी की तलवार से जुड़ा था। भारत निर्वाचन आयोग ने हेमंत सोरेन की विधानसभा रद्द करने की सिफारिश 25 अगस्त 2022 को राजभवन भेज दी। बावजूद इसके कानूनी राय के मामले को राजभवन ने हफ्ते भर के ज्यादा वक्त तक लटका दिया। राज्य में मुख्यमंत्री की बर्खास्तगी की खबरों के बीच अस्थिरता की स्थिति निर्मित हो गई। नतीजतन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को हाऊस ट्रेडिंग की अंदेशे के साथ पलायन को मजबूर होना पड़ा। पहले तो उन्होंने रांची के आसपास ही यूपीए विधायकों की बाड़ेबंदी की। लेकिन विधायकों के भाग निकलने के मद्देनजर उन्होंने छत्तीसगढ़ के रायपुर का रूख किया।

ऑफ प्राफिट, कोयला घोटाले और ब्लैक मनी इकट्ठा करने को लेकर सीबीआई, ईडी का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। इससे छुटकारा पाने के लिए छत्तीसगढ़ की शराबलॉबी सामने आयी है। सूत्र बताते हैं कि दिल्ली के दलालों और छत्तीसगढ़ की शराबलॉबी के संयुक्त कवायद इन दिनों सोरेन को बचाने के लिए जोरशोर से जुड़ी हुई है। इस लॉबी से मिले ठोस आश्वासन के बाद सोरेन मंत्रिमण्डल के कई मंत्री और विधायकों ने रायपुर का रुख किया। यहां एक रिसोर्ट में डेरा डालने के बाद सोरेन के मैनेजरों ने एक बड़ी ढील को अंजाम दिया है।

अभी तो रायपुर में विधायकों ने डेरा डालकर सरकार बचा ली, क्या भविष्य में भूपेश सरकार सोरेन सरकार की आवभगत करने के लिए तैयार रहेगी?

सूत्र बताते हैं कि इस डील में आयकर, ईडी और सीबीआई से बच निकलने की रणनीति बनाई गई है। इस रणनीति में इन तीनों ही केन्द्रीय एजेन्सियों को बदनाम करने की साजिश रची गई थी। सूत्र बताते हैं कि फोन टेपिंग और रणनीति लीक होने से बचने के लिए सोरेन के कुछ चुनिंदा मंत्रियों और मैनेजरों को रायपुर आना पड़ा। सूत्रों के मुताबिक छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल के बैनर तले साजिशों में जुड़ी

जिस रिसॉर्ट में ठहरे सोरेन के विधायक, वहां शराब की बोतलों से भरी मिली सरकारी गाड़ी

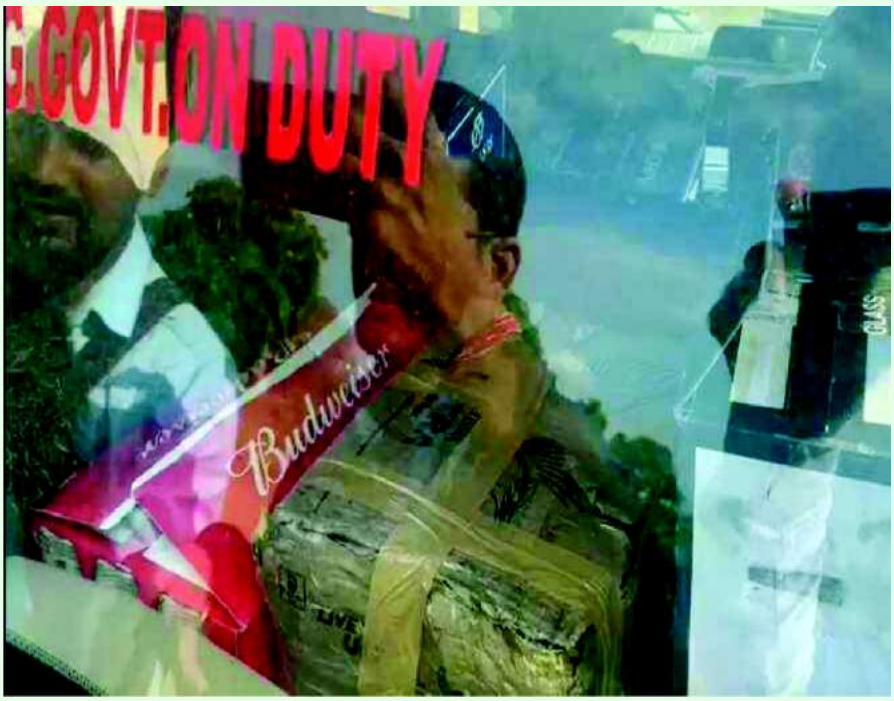

झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए अपनी कुर्सी बचाना चुनौती साबित हो रहा है। सत्ता बचाने का संघर्ष तो चल ही रहा है, विधायकों में टूट ना पड़ जाए, इसका भी ध्यान रखना है। इसी वजह से यूपीए के विधायक उस समय रायपुर के रिसोर्ट में ठहरे हुए थे। बीजेपी का आरोप है कि वहां पर विधायकों के लिए शराब का इंतजाम किया गया था। रिजार्ट में उनकी हर सुख सुविधा का पूरा ध्यान रखा गया था। इसे लेकर बीजेपी नेता और छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह ने छत्तीसगढ़ सरकार पर जमकर हमला बोला है। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह ने एक वीडियो ट्वीट करते हुए आरोप लगाया कि झारखंड के विधायकों को दारू-मुर्गा खिलाया गया। उन्होंने छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल पर निशाना साधा। रमन सिंह ने ये आरोप ऐसे समय में लगाया है जब सीएम बघेल खुद रायपुर के मेफेयर रिसॉर्ट जाकर झारखंड के विधायकों से मुलाकात की। ये मुलाकात करीब 45 मिनट तक चली। रमन सिंह ने ट्वीट करते हुए लिखा, भूपेश जी कान खोलकर सुन लीजिए! छत्तीसगढ़ अय्याशी का अड्डा नहीं है, जो छत्तीसगढ़ियों के पैसे से झारखंड के विधायकों को दारू-मुर्गा खिला रहे हैं। असम, हरियाणा के बाद अब झारखंड के विधायकों का डेरा, इन अनैतिक कार्यो के लिए छत्तीसगढ़ महतारी आपको कभी माफ नहीं करेगी।

छत्तीसगढ़ की शराबलॉबी ने आयकर, ईडी और सीबीआई को बदनाम करने की रणनीति पर काम भी शुरू कर दिया है। उधर डील फाइनल होने के बाद हेमंत सोरेन के सहयोगी 01 सितम्बर को वापिस रॉची लौट गए। इसके बाद रिसोर्ट में बीरानी छा

यह वही गाड़ी है जिसमें कीमती शराब भरी हुई है, जो झारखण्ड से आए विधायकों को रिसोर्ट में परोसी गई है। यह गाड़ी रिसोर्ट के बाहर मीडिया की नजरों में आयी है। इस गाड़ी के दिखने के बाद ही विपक्ष ने भूपेश सरकार पर मंहगी शराब परोसने और अय्याशी का अड्डा बनाने के आरोप लगाए है।

गई। बताया जाता है कि यह रिसोर्ट पूर्व केन्द्रीय मंत्री दिलीप रे का है। दिलीप रे वही केन्द्रीय मंत्री हैं जिनके खिलाफ सीबीआई ने कोयला मामले में उन्हें अदालत ने तीन साल की सजा सुनाई थी। हालांकि दिलीप रे फिलहाल जमानत पर हैं।

राज्यपाल की कार्यवाही से बचने के लिए मुख्यमंत्री सोरेन ने राज्यपाल के गृहनगर को ही बनाया ठिकाना, वजह जानकर हैरान हो जायेंगे आप

झारखण्ड के सीएम हेमंत सोरेन की विधायकी रद्द कर अलग कार्यवाही के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस को अपनी सिफारिश भेज दी है। अब सोरेन सरकार बचेगी या जायेंगी, इसका फैसला राज्यपाल के हाथों में है। संविधान के जानकार बताते हैं कि बर्खास्त होने की सूरत में भी सोरेन नये सिरे से सरकार गठन का प्रस्ताव राज्यपाल को भेज सकते हैं। इस तरह से भी कम से कम छः माह तक फिर मुख्यमंत्री बने रह सकते हैं। हालांकि इस बीच उन्हें विधानसभा सीट से निर्वाचन होकर विधायक बनना जरुरी है। जबकि संविधान के जानकारों का एक धड़ा यह भी कहता है कि ऑफिस ऑफ प्राफिट का मामला साबित होने के बाद सोरेन का दोबारा मुख्यमंत्री बनना संविधान का उल्लंघन होगा। इस मामले में राज्यपाल स्वविवेक से फैसला लेकर सोरेन की दोबारा चुनाव लड़ने पर रोक भी लगा सकते हैं। यदि ऐसा हुआ तो सोरेन दोबारा मुख्यमंत्री बनने से वंचित हो जायेंगे।

केन्द्रीय एजेन्सियों को बदनाम करने की साजिश रची गई थी। सूत्र बताते हैं कि फोन टेपिंग और रणनीति लीक होने से बचने के लिए सोरेन के कुछ चुनिंदा मंत्रियों और मैनेजरों को रायपुर आना पड़ा। सूत्रों के मुताबिक छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल के बैनर तले साजिशों में जुड़ी छत्तीसगढ़ की शराबलॉबी ने आयकर, ईडी और सीबीआई को बदनाम करने की रणनीति पर काम भी शुरू कर दिया है।

हालांकि खुद के मुख्यमंत्री पद के लिये अयोग्य ठहराये जाने की सूरत में हेमंत सोरेन अपनी पत्नी, पिता शिबू सोरेन और भाई सुनील सोरेन का नाम भी मुख्यमंत्री पद के लिये आगे बढ़ाया है। इस सियासी कशमकश के बीच हेमंत सोरेन का छत्तीसगढ़ की शराबलॉबी में जाना चर्चा में है। राज्यपाल रमेश बैस के गृहनगर रायपुर

यही है मेफेयर लेक रिसोर्ट। जहां पर हेमंत सोरेन सरकार के मंत्रियों और विधायकों को ठहराया गया था। इस आलीशान रिसोर्ट में विधायकों/मंत्रियों की आवभगत में भूपेश सरकार ने कोई कोर-कसर नहीं छोड़ी।

रिसोर्ट के अंदर सुख-सुविधाओं की तमाम इंतजाम थे। महंगी शराब से लेकर अय्याशी की सारी सुविधाओं के बीच इन विधायकों को ठहराया गया था। जिसका पूरा बंदोबस्त भूपेश सरकार ने किया। बताया जाता है कि इस रिसोर्ट में एक कमरे का एक दिन का किराया हजारों रूपये में हैं। भूपेश सरकार ने इन विधायकों की सुख-सुविधाओं पर प्रदेश के आदिवासियों का हक मारकर करोड़ों रूपये लुटाये।

में सोरेन कुनबे के दस्तक देने के मामले को नये सियासी समीकरणों से भी देखा जा रहा है। बताया जाता है कि झारखण्ड में सत्ता की सहभागिता से कांग्रेस को बाहर करने की रणनीति पर भी दांव पेचों का दौर शुरू हो गया है। सूत्र बताते हैं कि पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को और कमजोर करने के लिये झारखण्ड के सियासी संकट को हथियार बनाया गया है। दरअसल रायपुर में जो पटकथा लिखी गई है वह चौंकाने वाली है। सूत्रों के मुताबिक इसमें झारखण्ड की सत्ता से कांग्रेस को बाहर करने के प्लान पर मुंहर लगाई गई है। झारखण्ड में जेएमएम के साथ बीजेपी सत्ता में भागीदारी कर सकती है। आने

काँग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर भूपेश बघेल की नज़र

वाले दिनों में बीजेपी और कांग्रेस के कुछ नेताओं की भूमिका भी इस मामले में सामने आ सकती है। सूत्रों द्वारा बताया जा रहा है कि राहुल गांधी का करीबी होने का दावा करने वाले कुछ नेता उनकी आस्तीन में सांप की तरह फन फैलाये बैठे हैं। वो ईडी, सीबीआई और आयकर की संभावित कार्यवाही से बचने के लिए पर्दे के पीछे से बीजेपी को सहयोग कर रहे हैं। इसमें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का नाम सुर्खियों में है। राजनीति के पंडितों के मुताबिक सीएम बघेल की नजर कांग्रेस अध्यक्ष पद पर टिकी हुई है। कहा जा रहा

छत्तीसगढ़ को नही बनने देंगे अय्याशी का अड्डा-डॉ. रमन सिंह

रायपुर में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के मंत्री विधायक और मैनेजर जिस रिसोर्ट में डेरा डाले हुए थे। वहां बड़े पैमाने पर अवैध ब्राण्डों की शराब उपलब्ध कराई जा रही थी। आबकारी विभाग की सफेद बोलेरो गाड़ी को पत्रकारों ने रिसोर्ट के करीब ही पकड़ लिया। इस सरकारी गाड़ी के भीतर ब्राण्डेड शराब की कई पेटियां थी। इसका वीडियो वायरल होने के बाद बीजेपी समेत विपक्ष के कई नेताओं ने कांग्रेस और भूपेश बघेल को घेरा है। इन नेताओं ने ट्वीट कर भूपेश बघेल को चेतावनी दी कि छत्तीसगढ़ को अय्याशी का अड्डा नही बनने देंगे। पूर्व सीएम रमन सिंह और नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक समेत कई नेताओं ने ट्वीट कर बघेल को जमकर कोसा है। इधर इस घटना को बीते कई दिन हो जाने के बावजूद बघेल सरकार ने घटना की जांच कराना भी मुनासिब नही समझा। जबकि सरकारी वाहन में अवैध शराब के परिवहन का वीडियो देश भर में वायरल हो रहा है। राज्य की जनता भी बघेल सरकार की हकीकत से वाकिब होकर चिल्लाने लगी है कि उनकी खून पसीने की कमाई से झारखण्ड के विधायकों को अय्याशी कराई जा रही है। रिसोर्ट में सुरा सुंदरियों का इंतजाम रायपुर में डेरा डाले झारखण्ड के विधायकों और मंत्रियों को ऐश कराने का पूरा इंतजाम छत्तीसगढ़ की शराब लॉबी ने किया था। बताया जाता है कि रिसोर्ट में बार भी है। उसको पास शराब परोसने का लायसेंस है। इसमें बावजूद आबकारी विभाग की तरफ से सरकारी वाहन में अवैध रूप से शराब पहुँचाने का प्रबंध भी किया गया है। यह भी बताया जा रहा है कि जिस वक्त अवैध शराब से लदी इस गाड़ी का वीडियो वायरल हो रहा था, उस वक्त कई चर्चित कालगर्ल उनके साथ अज्ञात लड़कियां इस रिसोर्ट में मंडराती नजर आयी। उन्हें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि रिसोर्ट में इंट्री के लिए इंतजार कर रही हैं। हालांकि मौके पर पत्रकारों की मौजूदगी और सरकारी वाहन में वीडियोग्राफी का नजारा देखकर वे घटना स्थल से नदारद हो गई। कुछ पत्रकारों के कमरों में सुंदरियों का वीडियो भी कैद हुआ है। इन घटनाओं से साबित हुआ है कि आयकर, ईडी और सीबीआई जैसी संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार भी शामिल है। आखिर किसने निर्देश पर सरकारी वाहन से रिसोर्ट में शराब मुहैया कराई जा रही थी, इसकी जांच बेहद जरुरी है।

है कि मौजूदा दौर में छत्तीसगढ़ के आर्थिक सहयोग के कारण ही कांग्रेस पार्टी की तमाम गतिविधियां संचालित हो रही हैं। इन परिस्थितियों में बघेल अपनी राजनीति चमकाने में जुटे हुए हैं। फिलहाल झारखण्ड और छत्तीसगढ़ की राजनीति

डेढ़ साल में तीन बार रायपुर आए दूसरे राज्यों के मंत्री, विधायक

कांग्रेस शासित छत्तीसगढ़ पिछले डेढ़ वर्ष से पर्यटन की राजनीति का केंद्र बन गया है। इस छोटी अवधि में यह तीसरी बार है, जब विधायकों की कथित खरीद-फरोख्त से बचने के लिए कांग्रेस या उसके सहयोगी दल के विधायकों को यहां ठहराया गया है। 10 जून 2022 को राज्य सभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग की आशंका से हरियाणा कांग्रेस के विधायक रायपुर पहुंचे थे। अप्रैल, 2021 में असम विधानसभा मतगणना के पहले वीपीएफ के उम्मीदवारों को रायपुर लाया गया था। अब पड़ोसी राज्य झारखंड में सत्तारूढ़ संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) ने अपने 32 विधायकों को रायपुर लाया गया है। झारखंड से आए मेहमानों के लिए लगभग सभी 40 कमरे बुक कर लिए गए थे। आपको बता दें कि झारखंड की कुल निर्वाचित 81 विधानसभा सीटों में जेएमएम की 30 सीटें हैं और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कांग्रेस के समर्थन से सत्ता पर काबिज हैं।

यह तस्वीर उस समय की है जब राज्यसभा चुनाव के समय हरियाणा के विधायकों को रायपुर लाया गया था। उसके बाद भी हरियाणा में कांग्रेस का उम्मीदवार चुनाव हार गए थे और भूपेश बघेल की सारी तैयारी धरी की धरी रह गई थी।

गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में जब-जब मंत्रियों या विधायकों का डेरा लगा वहां की सरकारों पर संकट टला नहीं बल्कि बड़ा ही है। हरियाणा के सांसद रायपुर आये तो वहां कांग्रेस के लिए निर्धारित राज्यसभा उम्मीदवार हार गए। वहीं असम में भी यही स्थिति रही। इससे तो यही लगता है कि भूपेश बघेल इन मेहमानों की आवभगत तो काफी करते हैं। स्वागत और मेहमाननबाजी में तो कोई कोर कसर नहीं छोड़ते लेकिन स्थिति को देखते हुए रणनीति बनाने में असफल ही रहते हैं।

किस करवट बैठेगी यह आने वाले दिनों में तय होगी।

बताया जाता है कि छत्तीसगढ़ में ढाई-ढाई साल में मुख्यमंत्री पद के फार्मूले को लेकर कैबिनेट मंत्री टीएस सिंहदेव की चुनौती अभी खत्म नही हुई है। भले ही

भूपेश सरकार के खिलाफ बीजेपी का हल्लाबोल

छत्तीसगढ़ में बीजेपी 2023 विधानसभा चुनाव की तैयारी में नजर आ रही है। हाल ही में भाजयुमो ने प्रदेश में बेरोजगारी और बढ़ते अपराध को लेकर जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान भाजयुमो ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निवास का घेराव भी किया। पार्टी के बड़े नेताओं से लेकर कई कार्यकर्ता हजारों की संख्या में इस प्रदर्शन में शामिल हुए। वहीं, प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं की पुलिस से तीखी नोकझोंक भी हुई। छत्तीसगढ़ से हर जिले भर से करीब एक लाख कार्यकर्ता आंदोलन में शामिल होने के लिए पहुंचे।

छत्तीसगढ़ बन गया है माफियागढ़- अरूण साव

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि जब से छत्तीसगढ़

राज्य में कांग्रेस की सरकार बने चार साल बीत गये हो लेकिन कांग्रेस आलाकमान के वादे को निभाने के लिए टीएस सिंहदेव मुख्यमंत्री की कुर्सी हासिल करने के लिए अभी भी जोर आजमाईश में जुटे हैं। सूत्रों की माने तो छत्तीसगढ़ में नेतृत्व परिवर्तन

में कांग्रेस की सरकार आई है, ये मफियागढ़ बन गया है। बड़े-बड़े वादे किए गए थे, लेकिन एक भी वादा सरकार ने पूरा नहीं किया है। सरकार ने लोगों को सिर्फ ठगा है। नौकरी की पोल तो विधानसभा में खुल गई है। दस लाख नौकरियां देने की बात सरकार ने कही थी, लेकिन युवाओं को ठग दिया। उन्होंने कहा कि 28 अप्रैल 2002 के युवा मोर्चा के आंदोलन के बाद 15 साल बीजेपी की सरकार रही। आज इस आंदोलन के बाद राय में तीस साल तक बीजेपी की सरकार रहेगी। इस दौरान भाजपा ने मंच से नारा दिया- फिर एक बार भाजपा सरकार।

गंगाजल लेकर झूठा वादा करने का मांगेंगे हिसाब- डी.पुरंदेश्वरी

वहीं बीजेपी प्रदेश प्रभारी डी. पुरंदेश्वरी ने कहा कि कौरवों के पिता चाहते थे कि दुर्योधन कुरुक्षेत्र संग्राम में जीतकर वापस लौटे। उन्हें पता था कि उसे कोई मार सकता है तो वह भीम है। भीम को धृतराष्ट्र बुलाते हैं. कृष्णा को आलिंगन करने बुलाते है। कृष्ण रोकते हैं। भीम की प्रतिमा भेज दी जाती है। आलिंगन से भीम की प्रतिमा चूर-चूर हो जाती है। इस कहानी को इसलिए रख रही हूं क्योंकि आज छत्तीसगढ़ ऐसे ही धृतराष्ट्र के आलिंगन में है। इसलिए आज सबको भूपेश बघेल से जवाब मांगने जाना पड़ेगा। पुरंदेश्वरी ने कहा कि एक हाथ में गंगा जल लेकर झूठा वादा करने का हिसाब मांगा जाएगा।

रमन सिंह ने लगाया नारा, अबकी बार भाजपा सरकार

पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कहा कि

रायपुर में उमड़ा यह जन सैलाब उस समय का है जब बीजेपी ने भूपेश सरकार के खिलाफ हल्लाबोल कार्यक्रम आयोजित किया था। लाखों की संख्या में प्रदेश की जनता पहुंची थी। इस जन सैलाब को देखकर लगता है कि प्रदेश में भूपेश सरकार के खिलाफ जबर्दस्त माहौल है और आने वाले विधानसभा चुनाव में भूपेश बघेल सरकार का जाना तय है।

की सूरत में मुख्यमंत्री बघेल पाला बदल सकते हैं। वे कांग्रेस में अपने समर्थकों के साथ नई पारी की शुरूआत कर सकते हैं। ऐसे समय बीजेपी की सहानुभूति के पात्र बन जायेंगे। छत्तीसगढ़ से भी सत्ता की भागीदारी के मामले में कांग्रेस का पत्ता कट

भूपेश सरकार ने युवाओं के साथ छल किया है। सरकार के एक मंत्री कह रहे हैं कि बेरोज़गारी भत्ता देने का वादा नहीं किया। सरकार इस आंदोलन से इतना डर गई है कि सड़कों पर कंटेनर रख दिया है। झूठे वादे करके सरकार आई है। सरकार कहती है कि पांच लाख नौकरी दी गई, लेकिन जब विधानसभा में जवाब आता है तो 18 हजार नौकरियां देने की बात होती है। भृत्य के पदों के लिए दो-दो लाख आवेदन आ रहे हैं।

इस हुंकार से कुर्सी हिली, अगली हुंकार में सरकार गिरना तय- तेजस्वी

भाजयुमो राष्ट्रीय अध्यक्ष व सांसद तेजस्वी सूर्या ने कहा कि 04 सालों से विफल छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार से लाखों युवाओं का अधिकार मांगने आज रायपुर आगमन हुआ है। सभी युवाओं से मेरा अनुरोध है कि प्रदेश सरकार से न्याय मांगने के लिए आगे आएं और भ्रष्टाचार के विरोध में आवाज उठाएं। उन्होंने कहा कि कि भूपेश आपकी भ्रष्ट सरकार का समय समाप्त हो चुका है। छत्तीसगढ़ के लाखों युवाओं ने आपके छल-कपट से भरे प्रशासन को जड़ से उखाड़कर फेंकने का संकल्प ले लिया है। कांग्रेस का छत्तीसगढ़ से बोरिया बिस्तर बांधने का समय आ गया। बीजेपी के कार्यकाल में आईआईटी से विभिन्न राष्ट्रीय स्तर के शैक्षणिक संस्थान छत्तीसगढ़ में खोले गए थे। नालंदा जैसी भव्य लाइब्रेरी खोली गई थी। कांग्रेस

जायेगा। वैसे भी राजनीति में इधर से उधर पाला बदलना कोई नई बात नही है। लेकिन चिंता की बात यह है कि छत्तीसगढ़ जैसा समृद्धशाली प्रदेश मात्र चार साल में अपनी स्थिति पर कुठाराघात वाला वार झेल रहा है। किसान और आदिवासी बाहुल्य प्रदेश

सरकार नई शिक्षा योजनाएं तो छोड़ दीजिए, भ्रष्टाचार के कारण मौजूदा संस्थानों की देखभाल करने में भी असफल है।

वहीं भाजयुमो के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने कहा कि भूपेश सरकार डर चुकी है। पुलिस डर चुकी है। युवा मोर्चा अध्यक्ष बनने के बाद कई राज्यों के आंदोलनों में मैं भाग ले चुका हूं, लेकिन छत्तीसगढ़ के युवा मोर्चा ने जिस तरह से आंदोलन किया है, जिस तरह से सरकार को डरा दिया है। ऐसा आंदोलन मैंने नहीं देखा है। मैं हनुमान की जन्म स्थली कर्नाटक से आता हूं, आज श्री राम के ननिहाल आया हूं। ये संघर्ष करने का समय है, लाठी खाने का समय है, सरकार को उखाड़कर फेंकने का समय है। सूर्या ने कहा कि छत्तीसगढ़ के इतिहास में ये सरकार सबसे भ्रष्टतम सरकार है। भूपेश बघेल चीफ मिनिस्टर नहीं है, वह सोनिया गांधी के कलेक्शन मास्टर हैं। युवा मोर्चा तीन महीने का समय सरकार को दे रहा है कि सरकारी नौकरी के रिक्त पदों को भरे। अनियमित कर्मचारियों को नियमित किया जाए। युवा मोर्चा पीछे पड़कर ये काम करवाएगा। दिसम्बर महीने में युवा मोर्चा फिर एक बार हुंकार करेगा। इस हुंकार से कुर्सी हिल गई है। अगले हुंकार में सरकार गिरना तय है।

कार्यकर्ता चाहेगा तो कंटेनर को भी चिपका देगा-बृजमोहन

पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि विराट स्वरूप दिखना चाहिए कि राक्षसों का विनाश हो जाए। ये विराट स्वरूप दिखना चाहिए कि भ्रष्टाचारियों का सफाया हो सके। मुख्यमंत्री इतने डरपोक होंगे ये मालूम नहीं था। ये पहली बार किसी प्रदर्शन में हुआ है कि कंटेनर रोड में लगाए गए हैं। अगर कार्यकर्ता तय कर लेगा तो कंटेनर को भी चिपका देगा। वानरों ने इसी साहस से लंका पर विजय पाई थी। रावण तो विद्वान था, लेकिन ये सरकार भ्रष्टाचारी है। हमने नहीं सोचा था की पहचान अब भ्रष्टाचार और साजिशों के अड्डे के रूप में होने लगी है।

सिर्फ कागजों तक सिमटा भूपेश का छत्तीसगढ़ मॉडल

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का छत्तीसगढ़ मॉडल इन दिनों कारनामों

बेरोजगारों से गोबर बिकवा रही भूपेश सरकार - अजय चन्द्राकर

छत्तीसगढ़ में बढ़ती बेरोजगारी और बढ़ते अपराध के खिलाफ भारतीय जनता युवा मोर्चा ने रायपुर में जंगी प्रदर्शन किया। इस विरोध प्रदर्शन की अगुवाई भाजयुमो के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने की। भाजयुमो के इस प्रदर्शन में छत्तीसगढ़ बीजेपी के आला नेता भी मौजूद रहे। इस दौरान भाजपा प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, पूर्व सीएम रमन सिंह, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल, पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर, पूर्व मंत्री राजेश मूणत सभी ने कांग्रेस के खिलाफ राजधानी में हल्ला बोला। प्रदर्शन के दौरान पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, पूर्व मंत्री राजेश मूणत सहित कई कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। इस दौरान पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने कहा कि-

भारतीय जनता युवा मोर्चा रायपुर में बेरोजगारी के मुद्दे पर जंगी प्रदर्शन कर रही है, इस पर आप क्या कहेंगे ?

यह प्रदर्शन नहीं है। यह लाखों युवाओं का आक्रोश है, जिनको भूपेश बघेल ने ठगा है। भूपेश बघेल ने घोषणा पत्र के 36 वादों में से एक वादा भी आज तक पूरा नहीं किया है। सरकार चाहे तो किसी भी मंच पर हमारे साथ घोषणा पत्र को लेकर बहस कर ले। छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार ने बेरोजगारों को कहा आप जाकर गोबर बेचिए यही आपकी हैसियत है और यही हमारी नीति।

क्या बेरोजगार युवाओं के प्रदर्शन को रोकने प्रशासन ने सीएम हाउस का घेराव किया ?

डरी हुई सरकार ऐसे बैरिकेडिंग कर कंटेनर रखती है। लोकतंत्र में प्रोटेस्ट करने का हक सबको है। हजारों की संख्या में युवा मौजूद हैं। लेकिन कोई कानून व्यवस्था हाथ में नहीं ले रहा, कहीं तोड़ फोड़ नहीं हो रही है। सरकार को किस बात का डर है। भूपेश बघेल आखिर किस बात से डर रहे हैं। भूपेश बघेल को तो अमित साहू, तेजस्वी सूर्या, डी पुरंदेश्वरी, रमन सिंह और अरुण साव को बातचीत करने के लिए बुलाना था।

महंगाई को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ जल्द कांग्रेस भी दिल्ली में प्रदर्शन करने वाली है, इसको आप कैसे देखते हैं ?

भूपेश बघेल के खाते में सिर्फ और सिर्फ असफलता दर्ज है। कोई उपलब्धि दर्ज नहीं है, जिसको वह बता सके। भूपेश बघेल का सिर्फ एक ही एजेंडा है... हर बात पर केंद्र सरकार पर आरोप लगाना और भारतीय जनता पार्टी जैसा करे उसको कॉपी करना। इस सरकार की मौलिकता खत्म हो चुकी है।

क्या 2023 विधानसभा चुनाव में बेरोजगारी के मुद्दे पर युवाओं को भाजपा साधने की कोशिश कर रही है ?

आज राजधानी में जो युवा प्रदर्शन करने आए हैं। वह अनपढ़ युवा नहीं है। सभी पढ़े लिखे और समझदार हैं। आज वह सभी भूपेश बघेल से अपना हक मांगने आए हैं। युवा भाजपा ही नहीं बल्कि देश की फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है। जो देश के निर्माण के लिए काम करती है। मुख्यमंत्री कहते हैं कि उन्होंने 5 लाख युवाओं को रोजगार दिया लेकिन जब हम विधानसभा में सवाल लगाते हैं, तो मुख्यमंत्री चुप हो जाते हैं। विधानसभा में इतना झूठ बोलने वाला कोई मुख्यमंत्री नहीं है।

कि छत्तीसगढ़ में माफियाओं का राज होगा। युवाओं को नशे के आगोश में डुबाने वाली सरकार का क्या हश्र होना चाहिए? ऐसी सरकार को उखाड़कर फेंक देना चाहिए।

के लिए चर्चा में है। इस छत्तीसगढ़ मॉडल में लूट है, भ्रष्टाचार है, बेईमानी है, अत्याचार है, अन्याय है। इस मॉडल के नाम पर भूपेश बघेल पूरे राज्य को गर्त में ले जाने के लिए तैयार है भूपेश बघेल भले ही यह कहते नहीं थक रहे हैं कि

भ्रष्टाचार में छत्तीसगढ़ नंबर 1- धरमलाल

धरमलाल कौशिक ने कहा कि जनता ने अवसर दिया विकास के लिए, जनता ने अवसर दिया रोजगार देने के लिए, लेकिन सरकार ने राज्य को डुबोने का काम किया। सरकार ने साढ़े तीन सालों में 55 हजार करोड़ का कर्ज लिया। राज्य में आज कोई बच्चा पैदा होगा तो उसके माथे पर चालीस हजार का कर्ज होगा। युवाओं में सबसे ज्यादा हताशा छत्तीसगढ़ में है। भूपेश सरकार की नीति युवाओं को रोजगार देने के बजाय बेरोजगार करने की रही है। देश में भ्रष्टाचार पर सर्वे किया जाएगा तो पहले नंबर पर छत्तीसगढ़ आएगा। छत्तीसगढ़ में ऐसा कोई दिन नहीं जब चाकूबाजी की घटना ना हो। रायपुर का नया नाम चाकूपुर हो गया है। भूपेश सरकार का यही गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ है। भूपेश सरकार की वादाखिलाफी याद दिलानी है। शराबबंदी की घोषणा की गई थी, लेकिन क्या हुआ? वक्त है बदलाव का नारा उन्होंने दिया था, लेकिन अब लोग कह रहे हैं कि वक्त है पछतावा का। भूपेश सरकार को कहना है कि अब जनता आ रही है, गद्दी छोड़ो। वहीं केंद्रीय राज्यमंत्री रेणुका सिंह ने कहा कि युवा मोर्चा की ताकत और जोश से झूठ की नींव पर बनी सरकार को 2023 के उखाड़ फेंकना है। सीनियर पुलिस वाले जूनियर को आगे कर सभी हो गये थे। नदारत जिससे पुलिस की नाकामी का पोल इस धरना प्रदर्शन से खुल गई है। जिसकी वजह से ये प्रदर्शन कारी मुख्यमंत्री निवास तक पहुंचने में सफल रहे।

छत्तीसगढ़ मॉडल से प्रदेश का विकास हो रहा है लेकिन हकीकत में यह विनाश ही कर रहे हैं। कुछ कारनामें तो ऐसे हैं कि जिनका जिक्र करते ही सारी सच्चाई सामने आ जाती है। अपनी झूठी वाहवाही लूटने के चक्कर में भूपेश बघेल कांग्रेस हाईकमान के सामने भी गलत जानकारियां देते हैं।

अभिव्यक्ति की आजादी पर भूपेश बघेल का सख्त पहरा

शुरूआती 12 महीनों में भूपेश सरकार ने 22 पत्रकारों पर फर्जी प्रकरण बनवाये

छत्तीसगढ़ पत्रकारों के लिए सबसे असुरक्षित राज्यों में से एक है। प्रकाशित एड्ड रिपोर्ट के अनुसार अकेले छत्तीसगढ़ राज्य में राज्य बनने के बाद से 200 से अधिक पत्रकारों को समाचार छापने दिखाने के चलते उत्पन्न हुए विवादों के बाद जेल में डाला गया। जबकि 2018 दिसम्बर से नई कांग्रेस सरकार के सत्ता में आते ही महज 12 महीनों में 22 पत्रकारो पर फ़र्ज़ी पुलिस प्रकरण बनाये गए। वहीं 6 पत्रकारो को जेल भी भेजा गया व तीन पत्रकारों की थानों में निर्मम पिटाई हुई। इसी तरह पांच दूसरे पत्रकारों पर माफियाओं, आपराधिक तत्वों व राजनीतिज्ञों ने जानलेवा हमले किये। जबकि राज्य के निर्माण के बाद से अब तक करीब 6 पत्रकारो की निर्मम हत्या हो चुकी है। दुःखद तो यह रहा कि किसी भी हत्याकांड का खुलासा नही हुआ न ही कोई जिम्मेदार हत्यारा जेल भेजा गया। अब तक मिले अपुष्ट आंकड़ों में कार्य के दबाव और पुलिस प्रशासनिक एवं राजनीतिक माफियाओं के भयादोहन की वजह से राज्य में 20 पत्रकारों ने जान देने की कोशिश की। जबकि 8 ने आत्महत्या कर ली। इनमें से दो युवा पत्रकारों ने तो एक ही दिन में 17 जून, 2018 को क्रमशः अम्बिकापुर और जगदलपुर में आत्महत्या कर ली थी। वर्ष 2018 रायगढ़ जिले के युवा पत्रकार सौरभ अग्रवाल सहित राज्य में चार अन्य पत्रकारों ने लगातार हो रही बेजा पुलिस प्रताड़नाओ से तंग आकर अपनी जान देने की कोशिश की थी, जिनमें से दो पत्रकार तो बेहद गंभीर हालात से बचाए गए।

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इन दिनों पूरी तरह हिटलर के स्वरूप में आ गए हैं। अभिव्यक्ति की आजादी पर तमाम बंदिशें लगाकर लगातार मीडिया पर प्रहार कर रहे हैं। सच्चाई प्रकाशित करने वाले या प्रसारित करने वाले पत्रकारों को कानूनी रूप से परेशान किया जा रहा है। झूठे केस दायर कर पत्रकारों को गिरफ्तार कर जेल में डाला जा रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार का यह रवैया बिल्कुल ठीक नहीं कि पत्रकारों के ऊपर इस तरह से गलत आरोप लगाकर उन्हें हिरासत में ले लिया जाए। जरा सोचिए जब यह निर्दयी सरकार लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के साथ इस तरह से पेश आ रही है तो जनता की क्या मजाल कि वो इस सरकार के खिलाफ कोई आवाज उठाए। लोकतंत्र में राज व्यवस्था, न्याय व्यवस्था के बाद मीडिया ही बचा है जिसको कोई भी व्यक्ति अपने हिसाब से नहीं चला सकता। लेकिन भूपेश बघेल मीडिया को भी अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि पत्रकार उनके काली करतूतों को बिल्कुल न दिखाए और न ही छापे। बल्कि उनकी साफ और स्वच्छ छवि रोज अखबारों और चैनलों में प्रसारित करें। लेकिन यह कौन सा तरीका है जनाब? आप पत्रकारों को अपने हिसाब से चलाकर क्या साबित करना चाहते है? आज यदि आप एक सुनील नामदेव को गलत आरोप में अंदर करेंगे तो कल को न जाने कितने सुनील नामदेव पत्रकार बनकर अपनी आवाज बुलंद करेंगे। किस-किस को रोक सकेंगे आप? कितनों को जेल में रखेंगे आप? यह पहला वाक्या नहीं है जब बघेल सरकार ने पत्रकारों के साथ ऐसा व्यवहार किया हो। इससे पहले भी कमल शुक्ला सहित न जाने कितने पत्रकार बघेल की इस निर्दयिता का शिकार हुए हैं। यहां तक कि भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ के अंदर किए गए भ्रष्टाचार को जनता तक पहुंचाने पर मेरे खिलाफ भी केस दायर किया है। बघेल की इस भ्रष्टाचारी और तानाशाही सरकार में पत्रकारों की आवाज को दबाया जाता है, कुचला जाता है। मीडिया की आजादी को दबाकर तानाशाही रवैया अपनाया जाता है। जिस सराकर को भू-माफियाओं से प्रदेश को बचाना चाहिए वो सरकार इन्हीं माफियाओं की हितैषी बनी हुई हैं और मीडिया की आवाज को दबाना चाहती है। लगातार पत्रकारों पर होते एक के बाद एक हमलों के बाद पत्रकारों में दहशत का माहौल है। अगर छत्तीसगढ़ में पत्रकारों के विरुद्ध इसी तरह षडयंत्रपूर्वक अपराध दर्ज होते रहे तो कोई पत्रकार पत्रकारिता भी कर नहीं पायेगा। भ्रष्टाचार के खिलाफ लिख नहीं पायेगा। पत्रकारों पर हुई कार्यवाहियों को लेकर कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी छत्तीसगढ़ के पत्रकार कमल शुक्ला के मामले को लेकर भूपेश बघेल को कटघरे में खड़ा किया था और हिदायत दी थी कि भविष्य में पत्रकारों के साथ अनैतिक कार्यवाहियां न की जाये। निश्चित तौर पर यह भी सच है कि यदि पत्रकारों को लेकर भूपेश बघेल का यही रवैया रहा तो आने वाले चुनावों में कांग्रेस को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा।

किसान और खेती छत्तीसगढ़ की असल पूंजी हैं। इनकी बेहतरी और खुशहाली से ही राज्य को समृद्ध और खुशहाल बनाया जा सकता है। इसी का परिणाम है कि वर्तमान भूपेश सरकार ने प्रदेश में छत्तीसगढ़ मॉडल की रूपरेखा बनाई जिससे गांव गतिमान हो

जाए। लेकिन सरकार की सुस्त व्यवस्था और कुशासन से छत्तीसगढ़ मॉडल राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पुष्पित और पल्लवित नहीं कर सकी। गांव, ग्रामीणों और किसानों की तस्वीर और तकदीर में सुखद बदलाव दिखाई नहीं दिये। सरकार ने

भूपेश बघेल ने पत्रकारिता का गला घोंटा

तो वादा किया था कि छत्तीसगढ़ सरकार की गांव, गरीब, किसान, व्यापार और उद्योग हितैषी नीतियों से समाज के सभी वर्गो में खुशहाली लायेगी। धान और तेंदूपत्ता की देश में सबसे अधिक कीमत पर खरीदी, किसानों की कर्ज माफी, सिंचाई कर की

छत्तीसगढ़ में ईडी-आई टी की रेड ...

सूर्यकान्त ने मरवा दिया रे बाबा... जब ये अधिकारी चीखा-चिल्लाया

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह दोनों का चहेता है सूर्यकांत तिवारी

छत्तीसगढ़ में आईटी-ईडी की लगातार रेड से राजनैतिक, प्रशासनिक और व्यसायिक गलियारा बेहद सतर्क हो गया है। बावजूद इसके दोनों ही एजेंसियां काली कमाई पर शिंकजा कसने में कामयाब हो रही है। भले ही यह आरोप कई नेता लगा रहे हैं कि कांग्रेस शासित राज्यों में ही बीजेपी रेड करवा रही है। लेकिन आईटी ईडी की रेड में बरामद हो रही करोडों की नगदी और ब्लैकमनी के निवेश सामने आने से लोगों में आईटी ईडी पर भरोसा बढ़ने लगा है। उन्हें नजर आ रहा है कि एजेंसियां राजनैतिक भेदभाव से परे रहकर भ्रष्टाचार ख़त्म करने की मुहिम को अंजाम तक पहुँचाने में जुटी हैं। छत्तीसगढ़ में एक माइनिंग अफसर के यहाँ करोडों की नामी-बेनामी सम्पत्ति और निवेश के अलावा माइनिंग लीज़,पट्टे और खदानों के आवंटन से जुड़े दस्तावेजों की बरामदगी हुई है। गैर कानूनी क्रियाकलापों के जरिये पिछले दो सालों से चल रहे गोरखधंधे में शामिल नेताओं और उनके करीबियों के कारोबार में विभिन्न खनिजों की खदान आवंटन किस तरह से ब्लैकमनी का उत्पादन कर रहा है? यह एक डायरी उजागर कर रही है। डायरी एजेंसियों के लिए मील का पत्थर साबित हुई है। सूत्रों की मानें तो यह डायरी सूर्यकांत तिवारी के ठिकानों में हाल ही में हुई रेड के दौरान जब्त हुई थी। एक आलीशान घर में निवासरत अफसर की आँखे उस समय फटी की फटी रह गई, जब उसकी अलमारी से कुछ खास दस्तावेजों की बरामदगी चल रही थी। प्रदेश में माइनिंग का कीड़ा के सम्बोधन से जाने पहचाने जाने वाले इस अफसर के चेहरे की हवाइयां उड़ती देख टीम भी हैरत में पड़ गई। सूत्र बताते हैं कि इस अफसर ने चीखते हुए अपनी पत्नी से कहा कि सूर्यकान्त ने मरवा दिया रे बाबा। इसके बाद पूछताछ में अफसरों ने उस सूर्यकांत के बारे में कई जानकारियां हासिल की, जिसका नाम यह शख्स जप रहा था। सूर्यकान्त ने मरवा दिया रे बाबा। इस दिलचस्प नज़ारे की चर्चा रायपुर से लेकर दिल्ली तक हो रही है। बताया जाता है कि खदान आवंटन के खेल से संबंधित कई नामचीन नेताओं, अफसरों और कारोबारियों के दस्तावेज़ी चिट्ठे एजेंसियों के हाथ लगे हैं। गौरतलब है कि आयकर की टीम ने छत्तीसगढ़ में कई माइनिंग अफसरों के ठिकानों में इन दिनों दबिश जारी रखी है। राज्य में चल रही आईटी रेड से इस बार कई आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अफसरों के अलावा स्टील, कोयला और शराब कारोबारी समेत कुछ नामचीन ठेकेदारों के सतर्क होने की खबर आ रही है, जो सूर्यकांत के करीबी बताए जाते हैं। बताया जा रहा है कि सूर्यकांत के ठिकानों पर पिछले दिनों पड़े छापे में कुछ अफसरों और कारोबारियों की आमदनी, निवेश और रोजाना होने वाली कमाई का ब्यौरा मिला था। बताते हैं कि इस डायरी के एजेंसियों के हाथ लगने से कारोबारियों के अलावा अखिल भारतीय सेवाओं के कुछ अफसरों के निवेश संबंधी काले कारनामों का ब्यौरा भी जल्द सामने आ सकता है। ये पुराने नहीं बल्कि नए चर्चित अफसर बताए जा रहे हैं। कहा जाता है कि प्रदेश में आईटी-ईडी की छापेमारी में आई तेज़ी का कारण मुख्यमंत्री बघेल के करीबी सूर्यकान्त तिवारी के ठिकानों से बरामद हुए काले चिट्ठे ही हैं, जो आग में घी का काम कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक छत्तीसगढ़ में ब्लैकमनी के स्रोतों को खोजने के बाद आयकर ने उसके माझो इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट की जड़े भी खोदनी शुरू कर दी है। ताज़ा छापों को इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। फिलहाल ब्लैकमनी का सूर्या रायपुर-भोपाल-दिल्ली में एजेंसियों के दफ्तर का चक्कर काट रहा है।

माफी, सुराजी गांव योजना, राजीव गांधी किसान न्याय योजना और गोधन न्याय योजना के जरिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई जिंदगी मिलेगी। लेकिन हकीकत कुछ और बयां कर रही है। भ्रष्टाचार और लूट के कारण आज यह छत्तीसगढ़ मॉडल सिर्फ

खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं कर्मचारी

छत्तीसगढ़ के लाखों कर्मचारी प्रदेश की भूपेश बघेल सरकार से नाराज हैं। एक तरफ जहां राज्य में केन्द्र और अन्य राज्यों की तुलना में इन लाखों कर्मचारियों को मंहगाई एवं अन्यक भत्ते कम मिल रहे हैं वहीं लाखों कर्मचारी आज भी संविदाकर्मी या ठेके पर काम करने पर मजबूर हैं। जबकि 2018 में कांग्रेस के घोषणा पत्र में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि कांग्रेस की सरकार बनते ही संविदाकर्मियों का नियमित कर दिया जायेगा। आज चार साल से ज्यादा का समय हो गया है लेकिन इन कर्मचारी खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं। कर्मचारी सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाकर सरकार को कोस रहे हैं।

इसका ही परिणाम था कि छत्तीसगढ़ के लाखों कर्मचारी 22 अगस्त 2022 से दफ्तरों का काम छोड़कर हड़ताल में बैठ गए थे। इससे सरकारी काम काज बुरी तरह से प्रभावित हो रहा था। इसके बाद सरकार ने कर्मचारियों को हड़ताल वापस लेने के लिए अपील की। इसी बीच छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का कर्मचारियों से बातचीत का एक वीडियो वायरल हो रहा है।

कागजों भर में मिल रहा है। दरअसल छत्तीसगढ़ सरकार ने जो नया आर्थिक मॉडल अपनाया है, उसमें ग्रामीण विकास एवं औद्योगिक विकास के माध्यम से आर्थिक विकास और रोजगार के नए अवसर सुलभ होने थे। राज्य के किसानों

वायरल वीडियो में टीएस कह रहे हैं कि सरकार के पास पैसे देने की औकात नहीं है। वीडियो को पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने सोशल मीडिया पर शेयर कर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री स्वीकार कह रहे हैं कि सरकार के पास पैसे देने की औकात नहीं है। उन्होंने भूपेश बघेल को छत्तीसगढ़ का मिस्टर बंटाधार बताया है। रमन सिंह ने आरोप लगाया कि भूपेश बघेल के कुप्रबंधन ने छत्तीसगढ़ को कर्ज में डुबोकर दिवालिया कर दिया है। कर्मचारियों को ना वेतन देने के पैसे हैं और ना ही घोषणा पत्र के वादे पूरे करने को पैसे हैं।

महंगाई भत्ता की मांग करते हुए लाखों कर्मचारी हड़ताल पर बैठे थे। राज्य के कर्मचारी केंद्रीय कर्मियों की तरह 34 प्रतिशत महंगाई भत्ता मांग रहे थे। वर्तमान में राज्य के कर्मचारियों को 22 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिल रहा है। अगस्त में महंगाई भत्ता को 6 प्रतिशत बढ़ाकर 28 प्रतिशत कर दिया गया है। अभी भी कर्मचारी बचे 6 प्रतिशत महंगाई भत्ता के लिए अड़े हुए हैं। 96 कर्मचारी संगठनों का हल्लाबोला है। महंगाई भत्ता और गृह भाड़ा भत्ता बढ़ाने की मांग को लेकर कर्मचारी संगठन अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गए थे। कर्मचारियों की हड़ताल को देखते हुए छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार सकते में आ गई थी। कारण यह है कि हड़ताल की वजह से स्कूलों में पढ़ाई, न्यायिक प्रक्रिया, राजस्व मामलों के निपटारे से लेकर सामान्य सरकारी कामकाज ठप हो जाने का खतरा था। यह भी सच है कि ये कोई पहली हड़ताल नहीं थी, इससे पहले पिछले दिनों संगठन ने पांच दिनों के लिए हड़ताल की थी। उस समय अधिकारियों के साथ दो दौर की बातचीत में मांगों को माने जाने पर सहमति बन चुकी थी।

इस प्रमुख मांग को लेकर थी हड़ताल- छत्तीसगढ़ में सरकारी कर्मचारी सरकार से लगातार महंगाई भत्ता बढ़ाने की मांग कर रहे थे। कर्मचारी संगठन केंद्र सरकार की तरह 34 फीसदी महंगाई भत्ता देने की मांग राज्य सरकार से कर रहे थे बीते जुलाई महीने में भी कर्मचारी इस मांग को लेकर हड़ताल कर चुके थे तब कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 12 प्रतिशत था. हड़ताल के बाद सरकार ने उसे बढ़ा कर 18 प्रतिशत कर दिया था। लेकिन

कर्मचारी संगठन केन्द्र व दूसरी राज्य सरकारों की तरह 34 प्रतिशत महंगाई भत्ते की मांग कर रहे थे। इसको लेकर ही कर्मचारी बीते 22 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए थे।

टीएस सिंहदेव का कर्मचारियों से बातचीत का वीडियो वायरल- छत्तीसगढ़ में लाखों कर्मचारी महंगाई भत्ता की मांग को लेकर टीएस सिंहदेव को कहते हुए सुना जा सकता है कि आप लोगों का 5 से 6 हजार करोड़ रुपए बन रहा है। 05-06 हजार करोड़ रुपए देने की औकात सरकार के पास नहीं है। सिंहदेव कह रहे हैं कि मैं आप लोगों की तरफ से ही बोल रहा हूं। सरकार की तरफ से नहीं बोल रहा। आपकी समस्या को मैं भी समझ रहा हूं लेकिन पैसा नहीं है। आप लोगों को 40 हजार करोड़ रुपए तो दे ही रहे हैं। 05 हजार करोड़ और देने की स्थिति नहीं है। मैं घुमाने फिराने की बात नहीं कर रहा हूं, सही स्थिति बता रहा हूं। कर्मचारियों के दूसरे राज्य से महंगाई भत्ते की तुलना पर सिंहदेव ने कहा कि छत्तीसगढ़ में नरवा गरुआ गोबर ज्यादा हो गया है, कितना समझाएं।

का लगभग 09 हजार करोड़ रूपए का कृषि ऋण माफ होना था। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी, किसानों के ऊपर वर्षो से बकाया सिंचाई कर, राज्य के 05 लाख 81 हजार से अधिक किसानों को सिंचाई के लिए निःशुल्क एवं रियायती दर पर बिजली

अपने चुनावी वादों से मुकरे भूपेश बघेल

भूपेश सरकार अपने कुशासन से छत्तीसगढ़ को नशे का गढ़, अपराध का गढ़, भय का वातावरण निर्मित कर प्रदेश को अंधकार की ओर ले जा रही है। बघेल सरकार ने प्रदेश के युवाओं को ठगने का कार्य किया है। कांग्रेस पार्टी चुनाव के समय जन घोषणा पत्र में वायदा किया था कि बेरोजगार युवकों को बेरोजगारी भत्ता 2500 रूपये देने का वायदा किया था। बेरोजगार युवाओं को नौकरी देने का वायदा किया था लेकिन आज तक एक भी बेरोजगार युवकों को बेरोजगारी भत्ता नही मिला। रोजगार देने और दैनिक वेतनभोगियों, संविदा में कार्यरत सभी कर्मचारियों को नियमित करने की घोषणा की थी। सत्ता में आये चार साल से अधिक हो गये लेकिन अभी तक बेरोजगारों के हित में कोई कदम नही उठाया। कांग्रेस सरकार जनहित में किये गये अपने सभी वादों को भूल गये। कांग्रेस सरकार ने सत्ता पाने लोगों को झूठा प्रलोभन देकर उनसे छल किया है। अब अपने वायदों से मुकर रही है। बेरोजगार युवा रोजगार एवं बेरोजगारी भत्ता देने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन करने को मजबूर हैं। आपको बता दें कि चुनाव से पहले कांग्रेस ने प्रदेश की भोली-भाली जनता से बहुत सारे वादे किये थे। जनता ने इनके वादों पर भरोसा जताते हुए प्रदेश में भारी बहुमत से इनकी सरकार बनवाई। सरकार बनते ही प्रदेश की कांग्रेस सरकार जनता से किये अपने वादों से मुकर गई। युवाओं को रोजगार एवं बेरोजगारी भत्ता देने का वादा कर युवाओं का भरपूर समर्थन हासिल किया। सरकार बनते ही भूपेश सरकार रोजगार देना तो दूर युवाओं को 25 सौ रुपये बेरोजगारी भत्ता देने का जो वादा

किया था उससे भी मुकर गई। सत्ता के मद में चूर भूपेश सरकार शायद ये भूल गई है कि युवा अगर सरकार बना सकती है तो गिरा भी सकती है। भूपेश सरकार के वादाखिलाफी से बेरोजगार युवा काफी आक्रोशित हैं और समय आने पर प्रदेश की दगाबाज सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकेगी।

5 लाख नौकरियों का दें प्रमाण, नहीं तो दें इस्तीफा- डॉ.रमन सिंह

उपलब्ध कराना था। राजीव गांधी किसान न्याय योजना से किसानों के श्रम का सम्मान करना था तथा योजना के तहत किसानों को प्रतिवर्ष लगभग 5700 करोड़ रूपए की राशि आदान सहायता प्रदान करना था। इसका सीधा लाभ खेती-किसानी और

छत्तीसगढ़ पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने रोजगार के मुद्दे पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खुली चुनौती दी है। पूर्व सीएम एक बयान जारी करते कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को यह बताना चाहिए कि अपने चार साल के कार्यकाल मे पांच लाख युवाओं को कहां कौन से प्रदेश में नौकरी दी है? इससे पहले बघेल ने यह दावा किया था कि बीते

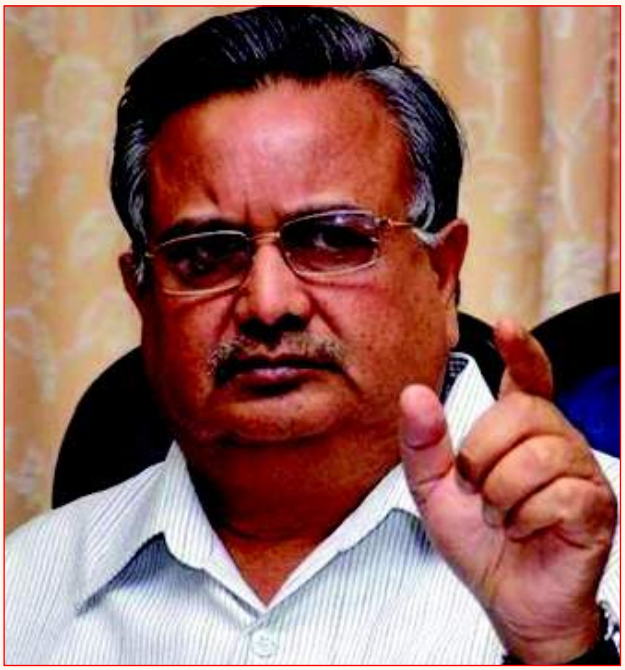

सालों में छत्तीसगढ़ के 4 लाख 65 हजार से अधिक लोगों को सरकारी और अर्द्धसरकारी कार्यालयों में कार्य करने का अवसर मिला है, इसके अलावा 30 हजार नौकरियां नए उद्योगों मे मिली हैं। डॉ रमन सिंह ने सीएम भूपेश बघेल पर तंज कसते हुए पूछा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 5 लाख युवाओं को नौकरी देने का महाझूठ फुल कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं। बघेल ने झूठ की पराकाष्ठा पार कर दी है और इसके लिए उन्हें युवा पीढ़ी से क्षमा याचना करना चाहिए कि छत्तीसगढ़ के युवा सपने चकनाचूर करने का महापाप उन्होंने किया है।

शराबबंदी पर भी पलटी बघेल सरकार- ऐसा नहीं है की भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली छत्तीसगढ़ सरकार का अपने वादों से मुकरने का यह पहला मामला है। इससे पहले सरकार ने 2018 विधानसभा चुनाव में वादा किया था कि सत्ता में आएंगे तो राज्य में पूर्ण शराबबंदी लागू होगी लेकिन इसके विपरीत सरकार ने स्वयं ही शराब की बिक्री शुरू कर दी। ऊपर से कोरोनाकाल काल में शराब पर कोरोना टैक्स के नाम से अधिभार लगाकर इस वित्तीय वर्ष में 200 करोड़ अतिरिक्त आय का लक्ष्य भी रखा। कांग्रेस ने जनता से लोक लुभावन वादे करके सत्ता हासिल कर ली लेकिन अब उन्हें पूरा करने से पीछे हट रही है। शराबबंदी के मुद्दे पर तो सीधा यू-टर्न ले लिया है। कहीं न कहीं उनकी मंशा साफ नही है। अपने लोगों को व्यक्तिगत फायदा पहुंचाने के लिए ऐसा किया जा रहा है।

किसानों को भूले भूपेश बघेल- कांग्रेस ने अपने 2018 के चुनावी मैनिफेस्टो में वादा किया था कि भाजपा सरकार सरकार द्वारा 2015-16 और 2016-17 में किसानों को बोनस का भुगतान नही किए जाने पर सत्ता में आए तो उनकी सरकार करेगी लेकिन अब उन्होंने यह भूला दिया है।

अवैध रेत खनन- कांग्रेस सरकार ने रेत खनन के काम का केंद्रीयकरण कर दिया है। जिसकी वजह से रेत के दाम में कई गुना वृद्धि हो गई है। इससे पहले रेत खनन की रॉयल्टी पंचायत और स्थानीय निकायों को जाती थी क्योंकि इसका संचालन भी वे ही करते थे, लेकिन अब सरकार इसे खुद कर रही है। खनन का पूरा काम भूपेश बघेल ने अपने लोगों के हवाले कर दिया है। एक परमिट में 10 से ज्यादा ट्रक रेत निकाली जा रही है और सरकारी खजाने को चूना लगाया जा रहा है। जितने शराब ठेकेदार थे अब रेत खनन का काम कर रहे है। तीन साल पहले तक 2500-3000 हजार रुपए रेत का दाम अब 10,000 हजार रुपए प्रति ट्रक तक पहुंच गया है।

किसानों को होना था। लेकिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का यह छत्तीसगढ़ मॉडल सिर्फ कागजों में सिमट कर रह गया है। जमीनी स्तर पर देखे को लोगों की, किसानों की आर्थिक हालत पहले से और ज्यादा खराब हो गई है।

मनीष सिसौदिया बनाम सीबीआई...

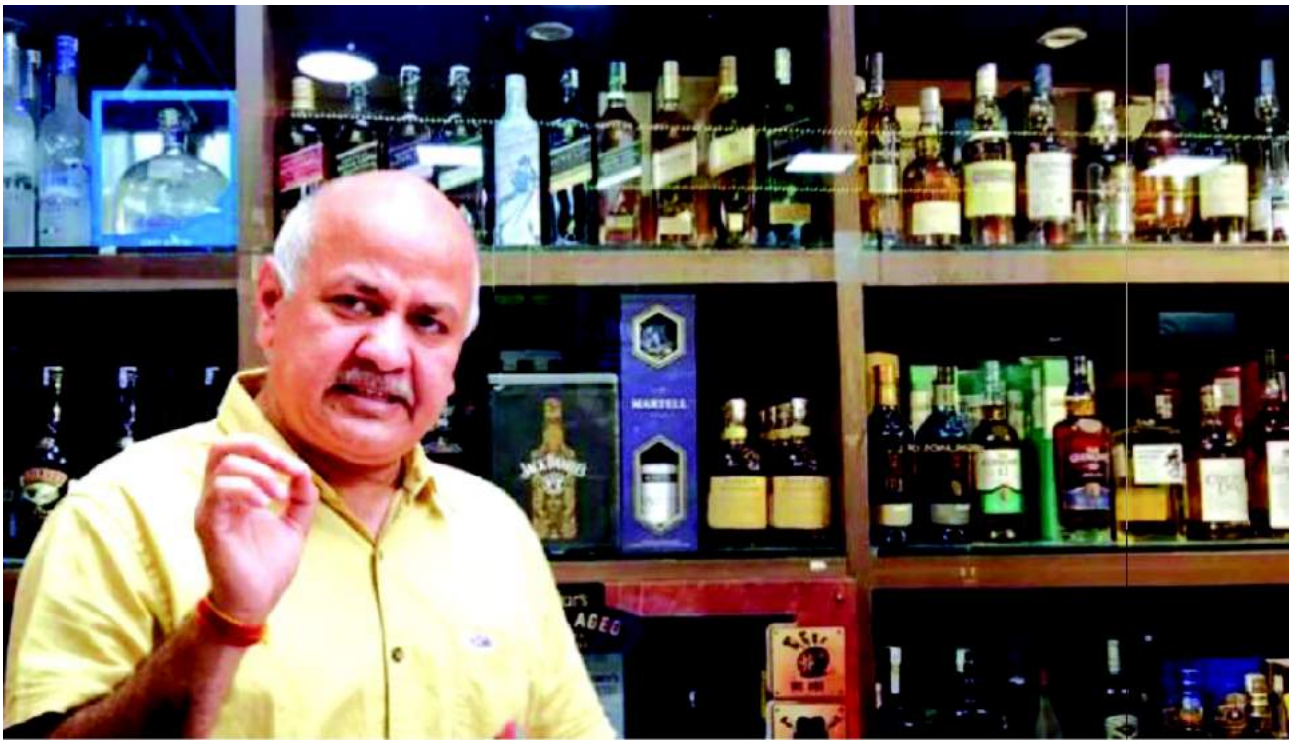

क्या बीजेपी के निशाने पर है दिल्ली सरकार?

समता पाठक

इस समय देश की राजनीति में दिल्ली की केजरीवाल सरकार सुर्ख़ियों में है। सुर्ख़ियों में इसलिए हैं कि दिल्ली उपमुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया के ठिकानों पर हाल ही में सीबीआई की छापे पड़े हैं। उन पर आरोप है कि उन्होंने आप सरकार की आबकारी नीति में बदलाव कर शराब व्यापारियों को ग़लत तरह से फ़ायदा पहुँचाया और सरकारी ख़ज़ाने को चूना लगाया। दिल्ली के नये उप राज्यपाल ने पद की ज़िम्मेदारी सँभालते ही मुख्य सचिव से रिपोर्ट तलब कर सीबीआई जाँच के आदेश दे दिये थे। बाद में आबकारी विभाग के 11 अधिकारियों को इसी मामले में उप राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने सस्पेंड भी कर दिया था।

इसके साथ ही विपक्षी नेताओं के घरों और ठिकानों पर सरकारी एजेंसियों के छापों की सूची में एक और नाम जुड़ गया है। यह नाम है आप नेता मनीष सिसोदिया का। ज़ाहिर है कि यह मामला आप के जी का जंजाल बन गया है। ख़ासतौर पर तब जबकि इस विभाग के मंत्री मनीष सिसोदिया के प्रेस कांफ्रेंस कर यह कहने के बाद कि शराब नीति में जो भी गड़बड़ी है उसके लिये पूर्व उप राज्यपाल अनिल बैजल ज़िम्मेदार हैं क्योंकि उन्होंने आख़िरी समय में आप सरकार की भेजी फ़ाइलों में हेर फेर किया था और बीजेपी के कुछ नेताओं को फ़ायदा पहुँचाया था। यानी मनीष सिसोदिया ने खुद ही यह मान लिया कि शराब नीति में कुछ न कुछ गड़बड़ तो

है। उन्होंने यह मान लिया था कि उप राज्यपाल की वजह से ही सरकारी ख़ज़ाने में जितना राजस्व आना चाहिये वो नहीं आया यानी चूना लगा। जबकि इसके पहले वो कह रहे थे कि शराब नीति में बदलाव के कारण राजस्व में इज़ाफ़ा हुआ और सरकार को अतिरिक्त 2000 करोड़ का लाभ मिल सकता है। तो क्या ये सारे दावे झूठे थे?

लेकिन छापे से ज्यादा यह मामला राजनीति का है। मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से ही विपक्षी नेताओं, दलों और सरकारों को सरकारी एजेंसियों ने निशाना बना रखा है। 2019 के बाद ऐसे छापे और विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारियाँ काफ़ी बढ़ी हैं। महाराष्ट्र में ही तीन बड़े नेता जेल में हैं। पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख, नवाब मलिक और शिवसेना के नेता और उद्धव ठाकरे के करीबी संजय राउत सलाख़ों के पीछे हैं। और उन्हें ज़मानत भी नहीं मिल रही है। दिल्ली में केजरीवाल के मंत्री सत्येंद्र जैन दो महीने से जेल की हवा खा रहे हैं। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार निशाने पर है। ठाकरे सरकार को गिराने के बाद अब उसका नंबर है।

19 अगस्त 2022 को दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर पर सीबीआई की रेड पड़ी थी। छापे के बाद मनीष सिसोदिया ने ऐसी आशंका भी जतायी थी कि दो-चार दिन में ही उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन अब तक उनकी आशंका गलत साबित हुई। मनीष सिसोदिया ने लुक आउट नोटिस जारी करने को लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोला। फिर अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की तरफ से सीबीआई के बाद ईडी के संभावित एक्शन का आरोप लगाया गया, लेकिन पता चला कि न तो लुकआउट नोटिस जारी हुआ है, न ही ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का कोई केस दर्ज किया है। सीबीआई के छापे मारने के बाद से हफ्ता भर से ज्यादा समय गुजर चुका है और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी के भारतीय जनता पार्टी से रोजाना दो दो हाथ करते देखा जा रहा है। बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस भी आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही है। देखा गया कि सीबीआई की छापेमारी के बीच बीजेपी की दिल्ली ब्रिगेड ने भी मोर्चा संभाल लिया था। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ साथ दिल्ली के सांसद प्रवेश वर्मा और मनोज तिवारी में तो अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार को महाभ्रष्ट साबित करने की तो जैसे होड़ ही मची रही। बीजेपी के हमलों को काउंटर करने के लिए मनीष सिसोदिया ने अपनी पार्टी तोड़ देने पर बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री बनाने के ऑफर का दावा कर दिया। मामला अभी ठंडा नहीं पड़ा कि 40 विधायकों को 20 करोड़ कैश के ऑफर का दावा किया जाने लगा। ऐसे ही ऑफर में आप नेताओं ने दावा किया कि अगर कोई विधायक किसी को रेफर करेगा तो उसे 25 करोड़ तक मिल सकते हैं। कुछ देर के लिए कई विधायकों के संपर्क में न होने को लेकर जबरदस्त माहौल भी बनाया गया, लेकिन बाद में सारे विधायक साथ आ गये और खुशी जताते हुए अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की कि बीजेपी की कोशिशों के

झूठे मामले में मनीष सिसौदिया को फंसाया जा रहा है– अरविंद केजरीवाल

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सिसोदिया को बेहद ईमानदार व्यक्ति बताते हुए कहा, सीबीआई जल्द ही एक फर्जी केस में मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करने वाली है। मनीष एक कट्टर ईमानदार आदमी हैं, जिन पर झूठे आरोप लगाये जा रहे हैं। अब देश में नया सिस्टम लागू हो गया है। पहले तय किया जाता है किसे जेल भेजना है, फिर उसके खिलाफ फर्जी केस बनाया जाता है। केजरीवाल ने कहा कि वह सिसोदिया को 22 साल से जानते हैं। उन्होंने कहा, अदालत के समक्ष यह मामला टिक नहीं पाएगा। वह पाक साफ साबित होंगे। आम आदमी पार्टी (आप) के नेता जेल जाने से नहीं डरते, क्योंकि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है। आम आदमी पार्टी (आप) के प्रमुख प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि उपराज्यपाल ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नीत केंद्र सरकार के इशारे पर सिसोदिया को फंसाने और आगामी विधानसभा चुनावों में पार्टी की चुनौती को कमजोर करने के लिए सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी का हवाला देते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि इस साल की शुरुआत में पंजाब विधानसभा चुनाव में आप की शानदार जीत के बाद से केंद्र, दिल्ली सरकार के मंत्रियों को फर्जी मामलों में फंसाने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा, ऐसा इसलिए हो रहा है, क्योंकि केंद्र तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में अरविंद केजरीवाल की बढ़ती लोकप्रियता से डरे हुए हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र को केजरीवाल की बढ़ती लोकप्रियता से ईर्ष्या है।

बावजूद उनके विधायकों को खरीदा नहीं जा सका।

भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ते तो अरविंद केजरीवाल 10 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि भ्रष्टाचार का मुद्दा कभी उनके भी गले पड़ जाएगा। न तो किसी को शक है और न ही अब तक किसी ने अरविंद केजरीवाल पर भ्रष्टाचार का आरोप ही लगाया है। कपिल मिश्रा के 02 करोड़ के रिश्वत वाले दावे का तो तब उनको संरक्षण दे रहे कुमार विश्वास ने ही खारिज कर दिया था। यहां तक कि दूध से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिये जाने के बावजूद योगेंद्र यादव ने भी कह दिया था कि कुछ भी हो जाये, ऐसा वो कभी नहीं मान सकते। वैसे भी राजनीति में आरोप प्रत्यारोप तो तब तक गंभीर नहीं माने जाते जब तक माफी मांगने की नौबत नहीं आ जाती।जब तक माफीनामा कोर्ट में जमा नहीं हो जाता और माफीनामे को कोर्ट की

मंजूरी नहीं मिल जाती। भला अरविंद केजरीवाल से बेहतर इसे कौन जानता होगा।

सीबीआई को स्वायत्तता कभी मिल पाएगी?

2011 में अन्ना हजारे के नेतृत्व में भ्रष्टाचार के खिलाफ चलाये गये आंदोलन के मुख्य कर्ताधर्ता अरविंद केजरीवाल ही थी। तब अरविंद केजरीवाल को टीम अन्ना का प्रमुख सदस्य कह कर बुलाया जाता रहा। ये तब की बात है जब केंद्र में कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए की मनमोहन सिंह सरकार थी और बीजेपी विपक्ष में हुआ करती थी। अन्ना के आंदोलन पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सपोर्ट होने के भी आरोप लगे थे और बीजेपी की बी टीम तक कहा जाता रहा। शायद इसलिए भी क्योंकि अन्ना आंदोलन की डिमांड को संसद में भी बीजेपी का समर्थन मिलता रहा। लोकसभा में तब की विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज ने अन्ना हजारे की तरफ से उठाये जा रहे मुद्दों का समर्थन किया था। अन्ना हजारे देश में कानून बनाकर लोकपाल की नियुक्ति की मांग कर रहे थे। बाद में सरकार के लोकपाल के ड्राफ्ट को टीम अन्ना ने जोकपाल करार दिया था और अपने हिसाब से जन लोकपाल का ड्राफ्ट तैयार किया। बाकी बातों के अलावा अरविंद केजरीवाल तब सीबीआई को स्वायत्त संस्था बनाने की मांग कर रहे थे और प्रधानमंत्री को भी लोकपाल के दायरे में लाने की मांग कर रहे थे। कालांतर में लोकपाल को औपचारिक रूप दिया भी गया और सुप्रीम कोर्ट के दबाव में नियुक्ति भी हुई, लेकिन सीबीआई को लेकर हुई बातें जहां की तहां रह गयीं।

तब अरविंद केजरीवाल और किरण बेदी एक ही मंच पर अन्ना हजारे के साथ देखे जा सकते थे। किरण बेदी ने तभी कहा था, हम करप्शन से आजाद देश चाहते हैं... इसके लिए आजाद सीबीआई चाहिये। और अरविंद केजरीवाल ने भी पूरे देश के सामने वादा किया था, हम आखिरी दम तक एक सशक्त लोकपाल को लेकर प्रतिबद्ध हैं। रामलीला आंदोलन के बाद जब राजनीतिक दल बनाने की बात हुई तो सबके रास्ते अलग हो गये। अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी बना ली और दिल्ली के मुख्यमंत्री बन गये। अन्ना हजारे अपने गांव रालेगण सिद्धि चले गये और दिल्ली में बीजेपी के चुनाव हार जाने के बाद किरण बेदी को पुडुचेरी का उपराज्यपाल बनाया गया था, लेकिन वहां से भी कार्यकाल खत्म होने के पहले ही बुला लिया गया।

सीबीआई रेड का क्या है पूरा मामला?

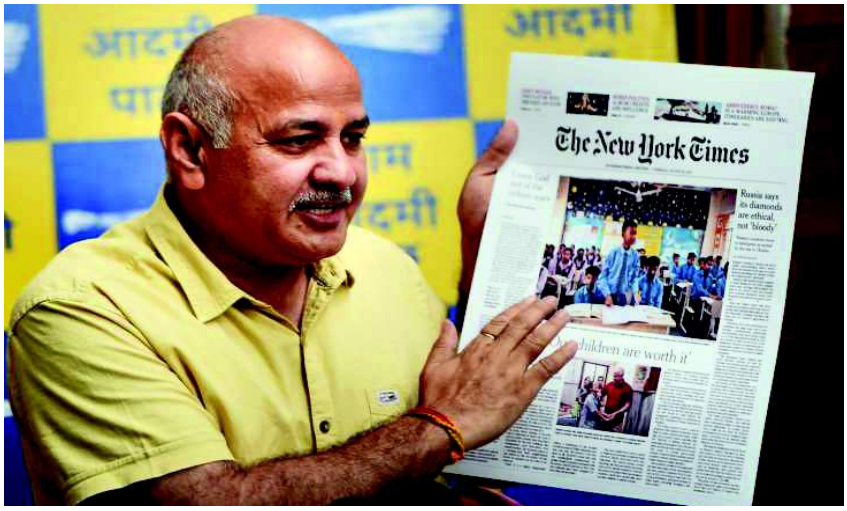

दिल्ली के मुख्य सचिव की जुलाई में दी गई रिपोर्ट के आधार पर सीबीआई जांच की सिफारिश की गई थी, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम 1991, कार्यकरण नियम (टीओबीआर)-1993, दिल्ली उत्पाद शुल्क अधिनियम-2009 और दिल्ली उत्पाद शुल्क नियम-2010 का प्रथम दृष्टया उल्लंघन पाए जाने की बात कही गई थी। रिपोर्ट में पाया गया था कि निविदा जारी करने के बाद शराब कारोबार संबंधी लाइसेंस हासिल करने वालों को अनुचित लाभ पहुंचाने के लिए जानबूझकर और घोर प्रक्रियात्मक चूक की गई। आरोप है कि राजकोष को नुकसान पहुंचाकर निविदाएं जारी की गईं और इसके बाद शराब कारोबार संबंधी लाइसेंस हासिल करने वालों को अनुचित वित्तीय लाभ पहुंचाया गया। सूत्रों ने दावा किया कि आबकारी विभाग ने कोविड- 19 वैश्विक महामारी के नाम पर लाइसेंसधारियों को निविदा लाइसेंस शुल्क पर 144.36 करोड़ रुपये की छूट दी। उन्होंने बताया कि लाइसेंस के लिए सबसे कम बोली लगाने वाले को 30 करोड़ रुपये की बयाना राशि भी तब वापस कर दी गई, जब वह हवाई अड्डा अधिकारियों से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्राप्त करने में विफल रहा था। विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट के आधार पर तैयार की गई आबकारी नीति, 2021-22 को पिछले साल 17 नवंबर से लागू किया गया था और इसके तहत निजी बोलीदाताओं को शहर भर में 32 क्षेत्रों में 849 दुकानों के लिए खुदरा लाइसेंस जारी किए गए थे। आरोप है कि सिसोदिया ने कथित तौर पर कोविड- 19 महामारी के बहाने निविदा लाइसेंस शुल्क पर शराब कारोबारियों को 144.36 करोड़ रुपये की छूट की अनुमति दी है। यह भी आरोप लगाया गया है कि आम आदमी पार्टी ने पंजाब चुनाव के दौरान इस पैसे का इस्तेमाल किया होगा।

सियासी उठापटक

नीतीश के बने रहने की होगी चुनौती

2024 के लोकसभा चुनाव हों या 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव, इन दोनों से पहले बिहार में शह-मात के नये-नये सियासी दांव नजर आएंगे। नीतीश फिर सब (राजद, कांग्रेस, हम, वाम व अन्य) के हैं, लेकिन मंत्रिमंडल में भागीदारी के बाद बिहार में इन सभी सहयोगी दलों के विधायकों को संतुष्ट रख पाना इतना आसान नहीं होगा।

अमित राय

नीतीश ने बिहार से दिल्ली को आंखें दिखाकर भले दिल्ली पर निगाहें टिका रखी हों लेकिन बिहार से दिल्ली तक आगे नीतीश के लिए सबके हैं या सबके बने रहने की राह आसान नहीं है। जाहिर है, 2024 के लोकसभा चुनाव हों या 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव, इन दोनों से पहले बिहार में शह-मात के नये-नये सियासी दांव नजर आएंगे। नीतीश फिर सब (राजद, कांग्रेस, हम, वाम व अन्य) के हैं, लेकिन मंत्रिमंडल में भागीदारी के बाद बिहार में इन सभी सहयोगी दलों के विधायकों को संतुष्ट रख पाना इतना आसान नहीं होगा। क्रांति की धरती बिहार में अगस्त ंति के दिन पलटी मार कर नीतीश कुमार ने सत्ता की बाजी एक बार फिर पलट दी। क्रांति का नया स्वर बुलंद कर दिया। नीतीश ने सियासी गुल खिला कर कमल को मुरझा दिया। हालांकि अब नीतीश की चुनौतियां और ज्यादा बढ़ गई हैं। नीतीश सबके हैं लेकिन क्या आगे भी वह बिहार से दिल्ली तक सबके बने रह पाएंगे, यही उनके लिए बड़ी चुनौती होगी। दरअसल, एक तरफ, नीतीश के सामने

सबके बने रहने की चुनौती है तो दूसरी ओर भाजपा के सामने सबका साथ, सबका विकास के मंत्र का टोटा है। बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान एक पोस्टर खूब चर्चा में था- नीतीश सबके हैं। यही पोस्टर फिर पटना की सड़कों पर नजर आया। गठबंधन से महागठबंधन की ओर पलटी मार कर नीतीश ने फिर से साबित कर दिया है कि वह सबके हैं लेकिन अब उनके सामने आगे भी सब के बने रहने की चुनौती होगी।

बिहार की सियासी बिसात पर नीतीश ने बाजी पलट दी है और शह-मात के खेल में गुल खिलाते हुए कमल को मुरझा दिया है। क्रांति की धरती बिहार से अगस्त क्रांति के दिन नई सियासी क्रांति की पटकथा लिखी गई। जाहिर है, 2024 के लोकसभा चुनाव हों या 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव, इन दोनों से पहले बिहार में शह-मात के नये-नये सियासी दांव नजर आएंगे। नीतीश के सामने अब बिहार से लेकर दिल्ली तक सबके बने रहने की चुनौती है तो भाजपा के सामने सबका साथ, सबका विकास के मंत्र का टोटा है।

बिहार में नीतीश की फिर से मुख्यमंत्री के पद पर अठवीं बार ताजपोशी हो गई। नीतीश ने लालटेन की लौ तेज कर दी है। अपने लिए भी उम्मीदें रौशन की हैं। बिहार में नए मंत्रिमंडल गठन से पहले ही स्पीकर और गृहमंत्री की कुर्सी को लेकर खींचतान की चर्चा तैर गईं। ऐसे में न केवल अकेले जदयू बल्कि राजद-कांग्रेस सरीखी पार्टियों के सामने भी भविष्य में अपने-अपने कुनबे को साथ बचाए रखने की चुनौती होगी।

नीतीश की चुनौतियां और चुनावों का दौर

बिहार में नीतीश की फिर से मुख्यमंत्री के पद पर अठवीं बार ताजपोशी हो गई। नीतीश ने लालटेन की लौ तेज कर दी है। अपने लिए भी उम्मीदें रौशन की हैं। बिहार में नए मंत्रिमंडल गठन से पहले ही स्पीकर और गृहमंत्री की कुर्सी को लेकर खींचतान की चर्चा तैर गईं। ऐसे में न केवल अकेले जदयू बल्कि राजद-कांग्रेस सरीखी पार्टियों के सामने भी भविष्य में अपने-अपने कुनबे को साथ बचाए रखने की चुनौती होगी। इन सभी के असंतोष को थामकर नीतीश के लिए सब के हैं...की चुनौती होगी। देर-सबेर महागठबंधन के विधायकों में यदि असंतोष पनपता है तो भाजपा के फायदा उठाने की सियासी कयासबाजी को नकारा नहीं जा सकता है। नीतीश के इस सियासी दांव को राजनीतिक गलियारे में भले

लोकसभा चुनाव में पीएम उम्मीदवारी के नजरिये से मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा हो, लेकिन नीतीश के लिए दिल्ली अभी दूर दिखती है। तब आरसीपी के कंधे की जरूरत न होगी। जाहिर है कि इस नई सरकार के लिए करीब तीन साल तीन महीने का कार्यकाल पूरा करने की राह निरापद नहीं है। ऐसे में बिहार के राजनीतिक परिदृश्य के नजरिए से भी नीतीश के सामने सबके हैं और सब के बने रहने की चुनौती होगी। नीतीश के सामने बिहार में राजकाज, विधि-व्यवस्था और आर्थिक पटरी पर विकास की रफ्तार को डबल इंजन के बगैर सरपट दौड़ाने की चुनौतियां भी होंगी।

किसी जमाने में जंगल राज और कर्मचारियों

पेंशनभोगियों को वेतन-पेंशन के लाले वाले इस राज्य ने इस कोरोना आपदा के दौरान समूचे देश के लिए मुफ्त वैक्सीन की राह खोली। अब अकेले अपने बूते इन चुनौतियों से नीतीश को बिहार को उबारना होगा। नीतीश के सामने स्पीकर, गृह मंत्री, मंत्रालयों के विभागों का बंटवारा जैसे मुद्दों पर भी महागठबंधन में संतुलन बनाये रखने की चुनौती होगी। यही कारण है कि बाकी मंत्रियों को शपथ नहीं दिलाई गई।

क्या नीतीश आगे भी सबके बने रह पाएंगे। क्या क्षेत्रीय क्षत्रप केसीआर राव, शरद पवार, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल विपक्ष के एकजुट पीएम उम्मीदवार के तौर पर नीतीश के नाम पर आसानी से मुहर लगा देंगे?

फिलहाल, नीतीश-तेजस्वी ने शपथ ली है। नीतीश की स्पीकर बदलने को लेकर भाजपा से जो अनबन हुई थी, वही स्पीकर की कुर्सी दूसरे पाले में देने की लाचारी भी दिख रही है।

नीतीश के लिए दिल्ली अभी दूर

नीतीश के इस सियासी दांव को राजनीतिक गलियारे में भले लोकसभा चुनाव में पीएम उम्मीदवारी के नजरिये से मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा हो,लेकिन नीतीश के लिए दिल्ली अभी दूर दिखती है। इसकी एक वजह यह है कि नीतीश के पीएम उम्मीदवार के कयास भले लगाए जाने लगे हों लेकिन सवाल उठता है कि क्या नीतीश आगे भी सबके बने रह पाएंगे। क्या क्षेत्रीय क्षत्रप केसीआर राव, शरद पवार, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल विपक्ष के एकजुट पीएम उम्मीदवार के तौर पर नीतीश के नाम पर आसानी से मुहर

लगा देंगे? क्षेत्रीय दलों की बात तो दूर क्या राष्ट्रीय और सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस इतनी आसानी से पीएम उम्मीदवारी के लिए अपनी दावेदारी छोड़ देगी? ऐसे में 2024 में दिल्ली के लिए शुरुआती दावेदारी या यूं कहें पीएम उम्मीदवारी को लेकर नीतीश के सामने सबके बने रहने की ही असली चुनौती होगी। हालांकि, शपथ ग्रहण करते ही नीतीश ने विपक्ष के पीएम उम्मीदवारी की ओर इशारा किया।

कुछ लोगों को लगता है कि विपक्ष खत्म हो जाएगा। हम लोग विपक्ष में आ गए हैं, 2024 में विपक्ष मन से लड़े। नीतीश ने लोकसभा चुनाव के लिए न केवल विपक्षी एकजुटता की वकालत की बल्कि विधानसभा चुनाव के दौरान अपने साथ चिराग मॉडल के जवाब में लोकसभा चुनाव में बदले के लिए शंखनाद भी कर दिया है।

भाजपा में सबका साथ का टोटा

नीतीश और भाजपा के बीच शह-मात का असली खेल तो आगे भी दिखने वाला है लेकिन रोचक यह होगा कि बिहार की जनता किसके साथ होगी, क्योंकि नीतीश-भाजपा को उम्मीद है कि दोनों सबके हैं।

नीतीश सब के हैं, के साथ भाजपा के सामने भी सब का साथ, सब का विकास वाले मंत्र का टोटा है। पंजाब, बिहार, महाराष्ट्र में एनडीए के साथियों का साथ छूटना इसकी मिसाल है। महाराष्ट्र का मामला सर्वोच्च अदालत में विचाराधीन है। ऐसे में इतना तय है कि नीतीश के ताजा सियासी दांव से बिहार की 40 लोकसभा सीटों की लड़ाई में भाजपा के सामने बड़ी चुनौतियां होंगी। लालू के राजद के माई (मुस्लिम-यादव) और नीतीश के सोशल इंजीनियरिंग के साथ-साथ वाम दलों-कांग्रेस के एकजुट गठजोड़ (यदि लोकसभा चुनाव तक महागठबंधन बरकरार रहता है) के सामने भाजपा मैदान में अकेले पड़ जाएगी और उसके सामने 2024 में 2014-2019 के नतीजे दोहराने की चुनौती होगी। जाहिर है, नीतीश और भाजपा के बीच शह-मात का असली खेल तो आगे भी दिखने वाला है लेकिन रोचक यह होगा कि बिहार की जनता किसके साथ होगी, क्योंकि नीतीश-भाजपा को उम्मीद है कि दोनों सबके हैं।

नीतीश कुमार दो-ढाई साल से ज्यादा किसी के साथ नहीं चल सकते

नीतीश कुमार दो-ढाई साल से ज्यादा किसी के साथ नहीं चल सकते और यह सरकार भी 2025 तक भी नहीं चलेगी। राजनीतिक गलियारे में पूर्व उपमुख्यमंत्री

एवं राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी का यह बयान चर्चा का विषय बना हुआ। राजनीतिक पंडित इसका विश्लेषण कर रहे हैं। नीतीश कुमार द्वारा पूर्व में लिए गए ऐसे फैसले की समीक्षा भी कर रहे हैं। इसके साथ ही इस बात भी मंथन कर रहे हैं कि नीतीश कुमार आखिर आरजेडी से ज्यादा कांग्रेस पर क्यों भरोसा कर रहे हैं और यह फैसला अभी ही क्यों लिया?

सरकार के कार्यकाल पर क्यों उठ रहे सवाल

सुशील कुमार मोदी ही नहीं कांग्रेस और राजद के नेता भी कुछ ऐसा ही सवाल कर रहे हैं। वे कानून व्यवस्था और सुशासन को लेकर चिंतित हैं। उनका कहना है कि नीतीश कुमार इस मुद्दे पर संभवतः समझौता नहीं करेंगे। इधर, सत्ता में आने के बाद आरजेडी के कार्यकर्ताओं को संयमित रखना संभव ही नहीं असंभव है। संभवतः यही कारण है कि सरकार बनने के बाद तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर अपने समर्थकों से खास अपील की है। अपने ट्वीट में उन्होंने समर्थकों से अपील किया है कि वे जश्न मनाना छोड़कर गरीब-गुरबा को गले लगाएं और ईमानदारी से उनकी समस्याओं का समाधान करें। दरअसल, तेजस्वी को यह पता है कि उनके कार्यकर्ता कैसे हैं। सत्ता मिलने पर वे किस प्रकार से उत्पात मचा सकते हैं। यही कारण है तेजस्वी बार-बार अपने कार्यकर्ताओं से संयमित रहने की अपील कर रहे हैं। क्योंकि उन्हें यह भी पता है कि कानून व्यवस्था का सवाल उत्पन्न होने पर नीतीश कुमार के साथ उनकी दूरियां बढ़ेगी।

लालू परिवार पर कानूनी वार को कैसे सहन करेंगे

इसके साथ ही लैंड फॉर जॉब घोटाले में लालू और उनकी पत्नी राबड़ी देवी के साथ साथ परिवार के कई सदस्य आरोपी हैं। सीबीआई और ईडी की कभी भी लालू परिवार पर कार्रवाई कर सकती है। ऐसी स्थिति उत्पन्न होने पर नीतीश कुमार के सामने अपना सुशासन बाबू का इमेज बचाने का खतरा होगा। तब नीतीश कुमार कैसे रिएक्ट करते हैं यह देखना होगा। राजनीतिक पंडितों का कहना है कि नीतीश कुमार के लिए वह क्षण अग्नि परीक्षा से कम नहीं होगा क्योंकि 15 सालों में उन्होंने जो सुशासन बाबू की छवि बनाया है यह उस पर हमला होगा। नीतीश कुमार 2017 में इसे ही आधार बनाते हुए महागठबंधन से अलग हुए थे। महागठबंधन से अलग होने के बाद उन्होंने कहा था कि जबसे राजद नेताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं तब से हम उनसे निवेदन कर रहे हैं कि वे कम से कम स्पष्टीकरण तो दे दें। हम खुद तेजस्वी से मिले थे और कहा था कि जो

छवि बनाई जा रही है, उसे उन्हें साफ करना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। स्थिति इतनी खराब हो गई कि मेरे लिए काम करना मुश्किल हो गया। हमने गठबंधन धर्म निभाया और उसे बचाने की कोशिश की। लेकिन अब मेरी अंतरात्मा इस बात की गवाही नहीं देती कि इसे जारी रखा जाए। वह स्थिति आज भी नहीं बदली है। नीतीश कुमार को सुशील मोदी ने उसे ही याद करवाते हुए कहा कि नीतीश जी आपके डिप्टी सीएम बेल पर चल रहे हैं। बताते चलें कि तेजस्वी यादव नीतीश कुमार की नई सरकार में बिहार के उपमुख्यमंत्री बने हैं।

नीतीश को क्यों है आरजेडी से ज्यादा कांग्रेस पर भरोसा

सरकार को लेकर नीतीश कुमार और तेजस्वी के बीच बातचीत तो बहुत पहले से चल रही थी लेकिन, नीतीश कुमार कांग्रेस को विश्वास में लेकर ही कोई फैसला करना चाह रहे थे। यही कारण है कि उन्होंने सब कुछ होने के बाद भी काफी समय तक कांग्रेस को हां का इंतजार किया और तेजस्वी को रुटे कांग्रेसी को मनाने की सलाह दी। नीतीश की सलाह पर ही तेजस्वी यादव कांग्रेस से अपने बिगड़े रिश्ते को ठीक किया। नीतीश कुमार आरजेडी से ज्यादा कांग्रेस पर शुरु से भरोसा करते रहे हैं। यही कारण है कि 2017 में गठबंधन तोड़ने से पहले नीतीश कुमार ने राहुल गांधी से मिलकर पूरे मामले में हस्तेक्ष करने को कहा था लेकिन, जब कांग्रेस इस मामले में कोई हस्तेक्षप नहीं किया तो वे अलग हो गए थे। नीतीश कुमार ने खुद इस बात की जानकारी पत्रकारों को दी थी। वर्तमान राजनीतिक स्थिति परिपेक्ष में नीतीश कुमार आरजेडी की जगह कांग्रेस का विधानसभाध्यक्ष चाहते हैं।

सोनिया गांधी को बनाया अभिवावक

जेडीयू से आरसीपी सिंह की विदाई के बाद भले ही सियासी हलचल तेज हो गई थीं लेकिन, इसकी पटकथा महीनों पहले ही लिखी जा चुकी थी, जिसके तार कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से जुड़े रहे। सूत्रों का कहना है कि सोनिया गांधी और नीतीश कुमार के बीच हुई फोन पर बातचीत में यह स्क्रिप्ट तैयार हो गई थी। सोनिया गांधी को जब यह पता चला कि नीतीश कुमार कोविड-19 संक्रमण से जूझ रहे हैं तो उनका हाल चाल जानने के लिए कॉल किया। कहा जा रहा है कि बातचीत के दौरान नीतीश कुमार ने सोनिया गांधी को भाजपा की तरफ से पड़ रहे दबाव के बारे में बताया और कहा कि भाजपा उनकी पार्टी तोड़ना चाहती है। तब कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी ने नीतीश कुमार को राहुल गांधी से बात करने के लिए कहा था। इसके बाद नीतीश कुमार राहुल गांधी से बात की। फिर इस मुद्दे पर तेजस्वी यादव ने भी राहुल गांधी से बात की तो पूरी पटकथा लिख गई। यही कारण था कि इस कार्य के लिए 09 अगस्त की का दिन चुना गया और 09 अगस की सुबह 11 बजे के आसपास ऐलान किया गया कि बिहार में खेला हो गया है।

चुनावों से पहले यह है भाजपा का बड़ा मास्टर स्ट्रोक

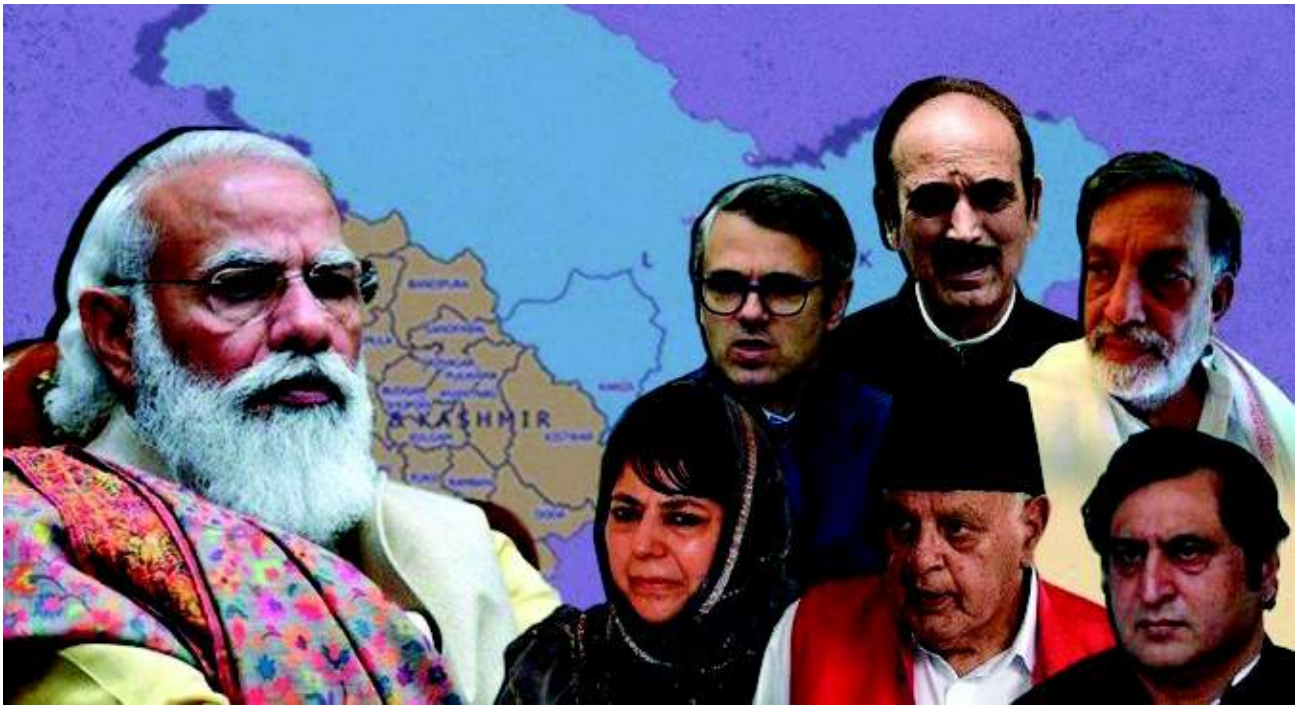

मणिशंकर पांडे

जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों की आहट शुरू हो गई है। अगर सब कुछ तय योजना के मुताबिक ही चलता रहा तो इस सीजन की बर्फबारी के खत्म होने के साथ ही जम्मू-कश्मीर में चुनाव हो जाएंगे। अनुमान के मुताबिक मार्च या अप्रैल महीने में मौसम अनुकूल होगा और जम्मू कश्मीर में चुनाव होंगे। फिलहाल जम्मू कश्मीर में नई मतदाता सूचियों का अंतिम और फाइनल प्रकाशन 25 नवंबर को हो जाएगा। ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि चुनाव आयोग अपनी तमाम तैयारियों के साथ राज्य में चुनाव की तारीखों का एलान जम्मू-कश्मीर के मौसम को देखते हुए कर सकता है। वहीं दूसरी ओर धारा 370 खत्म होने के बाद अब कोई भी व्यक्ति जम्मू-कश्मीर का मतदाता बन सकता है। राजनीतिक हलकों में यह एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। हालांकि जम्मू-कश्मीर की सियासत में इसका राजनीतिक दलों ने विरोध शुरू कर दिया है।

25 नवंबर को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन

जम्मू-कश्मीर में धारा-370 खत्म होने के बाद ही परिसीमन आयोग ने चुनावी तैयारियों के लिए सर्वे कराने की तैयारियां शुरू कर दी थी। अब परिसीमन आयोग की तैयारियों के साथ आई हालिया रिपोर्ट से अनुमान लगाया जा रहा है कि जल्द ही जम्मू-कश्मीर में चुनाव कराए जा सकते हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के मुख्य चुनाव अधिकारी हृदेश कुमार के मुताबिक 15 सितंबर को समग्र मतदाता सूचियों के मसौदे का प्रकाशन होगा। उसके बाद 10 नवंबर तक दावे और आपत्तियों का निराकरण किया जाएगा। मुख्य चुनाव अधिकारी के मुताबिक दावे और आपत्तियों के निराकरण के बाद 25 नवंबर को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। मुख्य चुनाव आयोग से जुड़े एक वरिष्ठ अधिकारी का मानना है कि चुनाव कराने से

पहले अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन सबसे महत्वपूर्ण होता है। जम्मू-कश्मीर में अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 25 नवंबर को कर दिया जाएगा। ऐसे में यह माना जाता है कि चुनाव आयोग अब चुनाव कराने की स्थिति में पूरी तरीके से तैयार है। विशेषज्ञों का मानना है कि क्योंकि अंतिम मतदाता सूची 25 नवंबर को प्रकाशित कर दी जाएगी, इसलिए यह तय है कि चुनावी रूपरेखा को पूरी तरीके से अमलीजामा पहना दिया गया है। उसके बाद चुनाव आयोग तारीखों का एलान कर सकता है।

सूत्रों के मुताबिक चुनाव आयोग 25 नवंबर के बाद चुनाव कराने की स्थिति में होगा। लेकिन दिसंबर से लेकर मार्च के शुरुआती दिनों में जम्मू-कश्मीर का मौसम चुनाव के लिहाज से मुफीद नहीं होगा। क्योंकि सर्दियों में घाटी में अच्छी खासी बर्फबारी भी होती है, ऐसे में चुनाव कराना किसी भी लिहाज से ठीक नहीं माना जा सकता है। सूत्रों का कहना है कि मार्च के अंतिम दिनों और अप्रैल के दौरान जब बर्फबारी कम होगी, तब चुनाव आयोग तारीखों का एलान कर सकता है। धारा-370 हटाने के बाद पहली बार कश्मीर में चुनाव होने हैं, तो चुनाव आयोग के लिए भी यह बड़ी परीक्षा होगी कि वोट प्रतिशत ज्यादा से ज्यादा रहे। ऐसी दशा में मौसम का अनुकूल होना बेहद जरूरी माना जाता है। इस लिहाज से यह माना जा रहा है कि चुनाव मार्च या अप्रैल में हो सकते हैं।

धारा-370 हटाने के बाद पहली बार कश्मीर में चुनाव होने हैं, तो चुनाव आयोग के लिए भी यह बड़ी परीक्षा होगी कि वोट प्रतिशत ज्यादा से ज्यादा रहे। ऐसी दशा में मौसम का अनुकूल होना बेहद जरूरी माना जाता है। इस लिहाज से यह माना जा रहा है कि चुनाव मार्च या अप्रैल में हो सकते हैं।

बढ़ेंगे 25 लाख मतदाता

परिसीमन आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक राज्य में तकरीबन 25 लाख मतदाताओं की संख्या के बढ़ने का अनुमान है। चूंकि धारा 370 की समाप्ति के बाद कश्मीर में कोई भी देश का नागरिक मतदाता बन सकता है। मतदाता बनने के लिए किसी भी तरीके के डोमिसाइल की आवश्यकता नहीं है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बढ़े हुए वोटरों और परिसीमन आयोग की नई व्यवस्था के मुताबिक जम्मू-कश्मीर में होने वाले चुनाव भाजपा के लिए मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकते हैं। जम्मू-कश्मीर से बाहर रहने वाले कश्मीरी पंडितों की बड़ी संस्था रूट्स इन कश्मीर के प्रवक्ता अमित रैना का कहना है कि चुनाव आयोग का यह फैसला स्वागत योग्य है। अमित कहते हैं कि जम्मू कश्मीर के डोमिसाइल होल्डर होने के बाद जब वह उत्तर प्रदेश के वोटर हो सकते हैं, तो उत्तर प्रदेश या बिहार का कोई व्यक्ति कश्मीर का

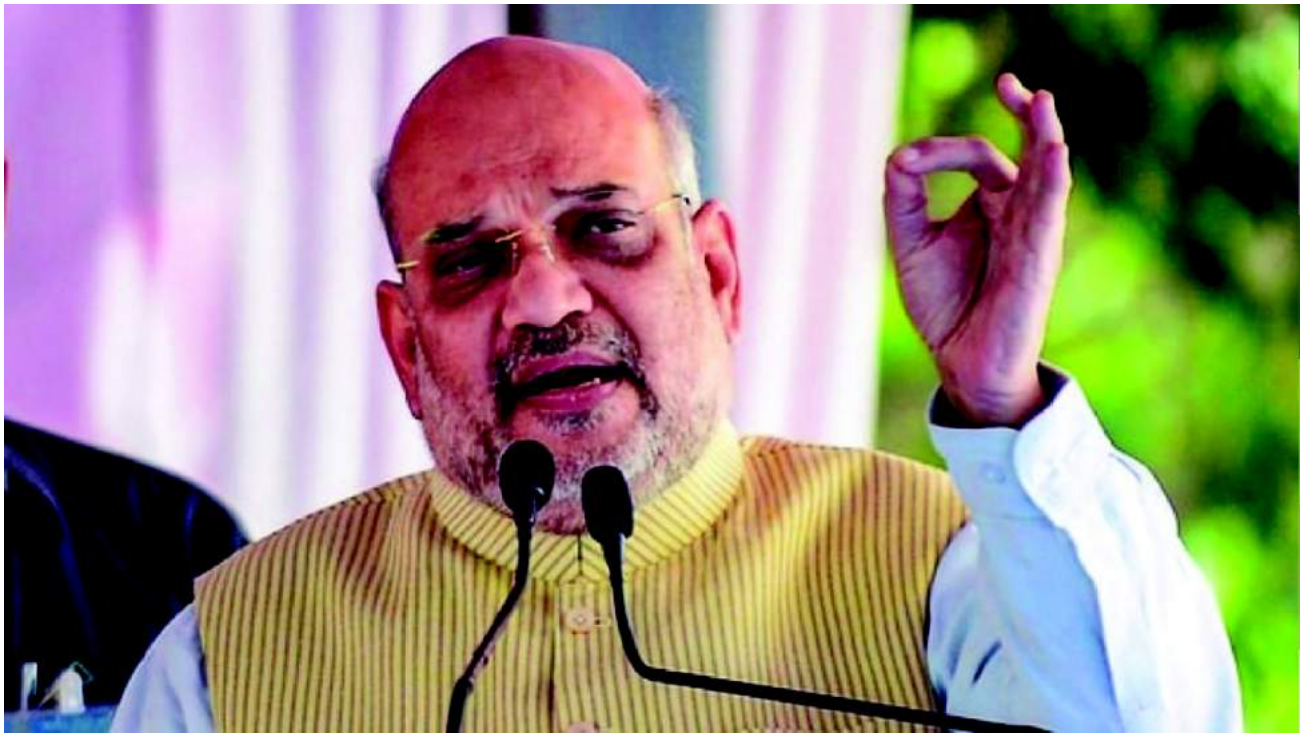

वोटर क्यों नहीं हो सकता है। वह कहते हैं कि धारा- 370 खत्म होने के बाद पूरे देश में जो वोटर बनने की व्यवस्था है वही कश्मीर में भी लागू हुई है। इसलिए 25 लाख वोटर बढ़ना कोई छोटी बात नहीं है। रूट्स इन कश्मीर से जुड़े लोगों का मानना है कि कश्मीर में आने वाले दिनों में एक बेहतरीन और स्थाई सरकार से लोगों का न सिर्फ जीवन यापन बेहतर होगा बल्कि पूरी व्यवस्था और मजबूत होगी।

हालांकि मतदाता सूची में बढ़ रहे 25 लाख नए वोटरों को लेकर सियासत भी गरम हो गई है। कश्मीर के राजनीतिक दलों ने इस पर केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया है। जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कहा कि भाजपा के लिए तो जम्मू कश्मीर एक प्रयोगशाला बन चुकी है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी के 25 लाख नए मतदाता बाहर से लाए जा रहे हैं। नई मतदाता सूची और बढ़ रहे मतदाताओं को लेकर नेशनल कांफ्रेंस ने भी हमला बोला है। नेशनल कांफ्रेंस के नेता तनवीर सादिक ने कहा कि 25 लाख नए वोटर बाहर से आकर यहां पर वोट करेंगे और फिर वापस अपने राज्य में चले जाएंगे। ऐसे में जम्मू-कश्मीर राज्य के लोगों को उनके मतदान से वंचित कर दिया जाएगा। हालांकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के मुख्य चुनाव अधिकारी का कहना है कि अनुच्छेद 370 की समाप्ति के बाद मतदाता बनने के वही सारे नियम कानून लागू हो रहे हैं जो कि सारे देश में लागू होते हैं।

जम्मू-कश्मीर में स्थानीय बनाम बाहरी के नाम पर राजनीति शुरू

महबूबा मुफ्ती ने आरोप लगाया कि इस फैसले से जम्मू-कश्मीर के लोगों की चुनाव में आस्था खत्म हो जाएगी। अनुच्छेद-370 के खात्मे के साथ ही हाशिए पर आ चुके कश्मीरी दल इस मुद्दे पर एकाएक आक्रमक होते नजर आए। इंटरनेट मीडिया पर भी इस बहस को गर्म करने का प्रयास किया गया। स्पष्ट है कि यह दल लोगों की भावनाओं को उकसाकर खोया आधार पाने का प्रयास करेंगे। जम्मू-कश्मीर में बसे दूसरे राज्यों के लोगों को भी वोट का अधिकार मिलने के साथ ही कश्मीर की सियासत गर्म हो गई है। कश्मीर केंद्रित दलों सहित कांग्रेस भी इसका विरोध कर रही है। इन दलों ने स्थानीय बनाम बाहरी के नाम पर राजनीति शुरू कर दी है। इस मुद्दे पर नेशनल कांफ्रेंस के अध्यक्ष डॉ. फारूक अब्दुल्ला ने भाजपा छोड़ सभी छोटे-बड़े दलों की बैठक बुलाई। पीडीपी प्रधान

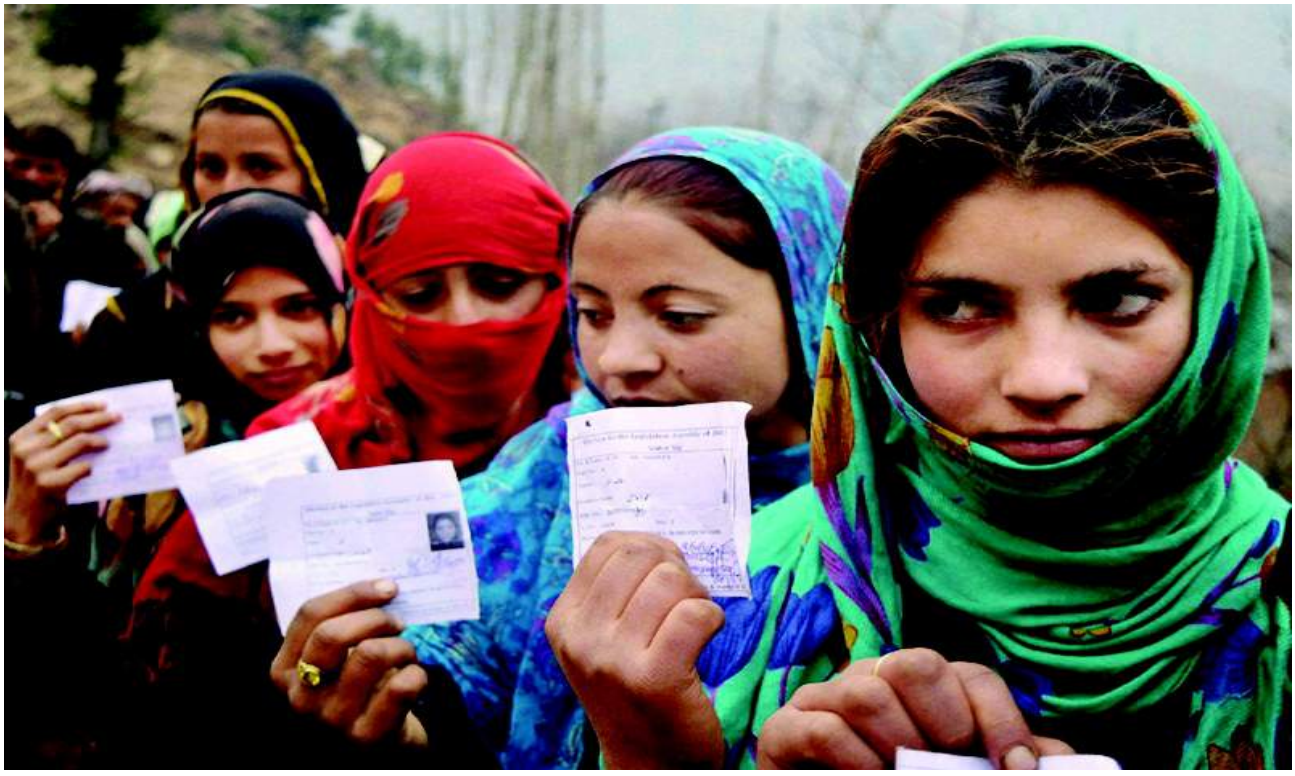

महबूबा मुफ्ती इसे भाजपा का राजनीतिक षड्यंत्र बता रही हैं।

अनुच्छेद-370 की समाप्ति के साथ ही जम्मू-कश्मीर में केंद्रीय कानून लागू हो गए हैं। इसके तहत देश के अन्य राज्यों की तरह जम्मू-कश्मीर में भी अन्य राज्यों से आकर बसे नागरिक मतदाता सूची में नाम शामिल करवा सकेंगे, बशर्ते उनका नाम मूल राज्य की मतदाता सूची में शामिल न हो। बुधवार को मुख्य निर्वाचन अधिकारी की इस संबंध में घोषणा के साथ ही कश्मीरी दलों ने इस विषय को तूल देना शुरू कर दिया। अनुच्छेद-370 के खात्मे के साथ ही हाशिए पर आ चुके कश्मीरी दल इस मुद्दे पर एकाएक आामक होते नजर आए। इंटरनेट मीडिया पर भी इस बहस को गर्म करने का प्रयास किया गया। स्पष्ट है कि यह दल लोगों की भावनाओं को उकसाकर खोया आधार पाने का प्रयास करेंगे।

महबूबा ने भाजपा को कोसा

पीपुल्स डेमोटिक पार्टी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने आरोप लगाया कि इस फैसले से जम्मू-कश्मीर के लोगों की चुनाव में आस्था खत्म हो जाएगी। वर्ष 2024 के संसदीय चुनावों के बाद भाजपा भारतीय संविधान को भी समाप्त कर देगी। वह राष्ट्रध्वज तिरंगे के जगह भगवा झंडा करेगी। यह जम्मू-कश्मीर के लोगों को राजनीतिक रूप से कमजोर बनाने और भाजपा के जम्मू कश्मीर में सत्ता सुनिश्चित करने का केंद्र सरकार का नया हथकंडा है। इससे पहले 1987 में भी चुनाव में धांधली हुई थी। ऐसे फैसलों की वजह से ही आज कश्मीर के लोग झेल रहे हैं।

लोगों की भावनाओं को ठेस

कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जीए मीर ने कहा कि यह एक दल विशेष के राजनीतिक एजेंडे को पूरा करने के षड्यंत्र का हिस्सा है। केंद्र को जम्मू-कश्मीर के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने, उन्हें राजनीतिक रूप से कमजोर करने के बजाय सशक्त बनाना चाहिए।

यह हुआ है बदलाव

अनुच्छेद-370 की समाप्ति के साथ जम्मू-कश्मीर में केंद्रीय कानून लागू हो गए हैं। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और 1951 के तहत कोई भी भारतीय नागरिक देश के किसी भी भाग में (जहां वह चाहे कुछ समय के लिए ही रह रहा हो) संबधित नियमों को पूरा करते हुए बतौर मतदाता खुद को पंजीकृत करा सकता है। अब यह कानून जम्मू-कश्मीर में पहली बार लागू हो रहा है और कश्मीरी दल इसे सियासी रंग दे रहे हैं। इसके नए नियम के तहत अब जम्मू-कश्मीर में तैनात सुरक्षा बलों के जवान डाल सकेंगे वोट। ऐसे में अनुच्छेद-370 समाप्त होने के बाद पहली बार बन रही मतदाता सूचियों में करीब 25 लाख नए मतदाता जुड़ेंगे। इसमें काफी संख्या युवा भी होंगे।

जब कटनी के हर घर और हर दुकान में लहराया था तिरंगा

मनोज कुमार श्रीवास्तव

देश के आजाद होने के पहले ही कटनी जिले के नागरिकों ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा के प्रति अगाध प्रेम, राष्ट्रीयता और देशभक्ति का जज्बा दिखाते हुए, यहाँ के हर घर, हर दुकान और प्रतिष्ठान में तिरंगा फहरा दिया था। इस अद्‌भुत और ऐतिहासिक दिन का साक्षी बनी थी इतिहास में दर्ज 26 जनवरी 1930 की तारीख। इस दिन कटनीवासियों ने संपूर्ण स्वराज के संकल्प का हर्षनाद कर गली-चौराहों में जुलूस निकाला था।

आजादी के 75वें वर्ष अमृत महोत्सव में 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान में कटनी का हर नागरिक तिरंगा फहराने के लिए संकल्पित है। आज से करीब 92 साल पहले भी कटनीवासियों ने 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वाधीनता के संकल्प के साथ हर घर, हर दुकान में राष्ट्रीय तिरंगा फहराया था। इस दौरान जुलूस निकाला गया था और जुलूस में शामिल हर देश भक्त के हाथ में आन-बान और शान का प्रतीक तिरंगा लहरा रहा था। इसी जोश और जज्बे के साथ एक बार फिर कटनीवासी हर घर तिरंगा अभियान में हर घर, हर संस्थान में राष्ट्रीय ध्वज फहरा कर आजादी के पुरोधाओं का पुण्य-स्मरण कर उनकी शहादत को नमन करेंगे। स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक संस्थानों सहित निजी प्रतिष्ठानों व्यापारिक और सामाजिक संगठनों ने भी आजादी के 75वें वर्ष के इस अनूठे अभियान में सहभागी बनकर हर घर तिरंगा अभियान का हिस्सा बनने का संकल्प लिया है।

कटनी की पवित्र धरा ने देशभक्ति की अलख जगाने वाले कई सूरमाओं और

आजादी के दीवानों को पैदा किया है, जिन्होंने देश को आजाद करने में अपने प्राणों की आहूति दे दी। देश के स्वातंतत्र्य समर में सहभागी बने हर सेनानी ने देश के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। किसी के भी योगदान को कम या अधिक के पैमाने में आंका नहीं जा सकता। इनमें से कई अमर सेनानी और क्रांतिकारी गुमनाम हैं।

समूचे देश के साथ कटनी में भी 26 जनवरी 1930 को पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। कटनी, सिहोरा, सिलौडी, उमरियापान, विजयराघवगढ़ आदि स्थानों पर तिरंगा फहरा कर और जुलूस निकाल कर आजादी के दीवानों ने पूर्ण स्वाधीनता का संकल्प लिया था। उस दिन कटनी तहसील (मुड़वारा) की जनता में अपूर्व उत्साह था, शहर में विशाल जुलूस निकाला गया, हर व्यक्ति के हाथ में तिरंगा था। बच्चों और महिलाओं ने इस विशाल जुलूस को घरों की छत से देखा। भारत माता के जयकारे और वंदे-मातरम के गगन भेदी उद्घोष से पूरा शहर गूँज उठा था। जुलूस की समाप्ति पर शहर के जवाहर चौक में एक आम सभा हुई थी, जिसमें बड़ी ही ओजस्वी वाणी में स्वाधीनता का घोषणा-पत्र पढ़ कर जन-समूह को सुनाया गया था। साथ ही जनता को स्वाधीनता का संकल्प भी दिलाया गया था।

आजादी के प्रति कटनी की जनता को जागरूक और प्रेरित करने में बाबू हनुमंत राव, श्री राधेश्याम, पं. गोविंद प्रसाद खम्परिया, नारायण दत्त शर्मा, ईश्वरी प्रसाद खंपरिया, अमरनाथ पांडे, पूरनचंद्र शर्मा, भैया सिंह ठाकुर, पं. नारायण प्रसाद तिवारी और खुशालचंद्र बिलैया की महती भूमिका रही थी। अंग्रेज सरकार की दमनकारी नीतियों की वजह से कटनी के कई सेनानी शहीद होने और अंग्रेजों की प्रताड़ना झेलने के बाद भी गुमनाम रह गये। लेकिन कटनीवासियों ने अपने गुमनाम शहीदों की स्मृतियों को न केवल अक्षुण्ण रखा है, बल्कि उनके चरणों में श्रद्धा-सुमन भी अर्पित किये और उनकी शहादत को सदैव याद किया।

जल जीवन मिशन में 26 माह में पहुँचा 52 लाख घरों में जल

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का देश की ग्रामीण आबादी के लिए राष्ट्रीय जल जीवन मिशन ऐसा वरदान है जो इनकी पेयजल की कठिनाइयों को पूरी तरह दूर कर देगा। आजादी के बाद श्री मोदी ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने ग्रामीण परिवारों की पेयजल व्यवस्था की बड़ी कठिनाई को समझा, उस पर गंभीरता से चिंतन किया और निदान के लिये जल जीवन मिशन को मूर्तरूप दिया।

जल जीवन के लिए जरूरी है। सर्दी, गर्मी अथवा वर्षा का प्रभाव झेलकर भी पेयजल की व्यवस्था करना इंसानी मजबूरी है। हम सभी ने देखा है कि ग्रामीण परिवारों में पेयजल की व्यवस्था की जिम्मेदारी घर की महिलाओं पर रहती है। नदी, तालाब, कुआँ, पोखर, हैण्डपंप जैसे पानी के स्त्रोत कितनी भी दूर हों लेकिन पानी लाने का काम माँ, बहन और बेटियों को ही करना होता है। इन्हें अब मिशन के जरिये घर पर ही नल से जल मिलना शुरू हो गया है।

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश में मिशन में कार्य प्रारंभ करवायें। निरन्तर प्रगति की समीक्षा करते हुए बेहतर और कार्यो को शीघ्र पूरा कर ग्रामीणों तक सुविधा पहुँचाने के लिए प्रेरित किया। मुख्यमंत्री श्री चौहान के सतत मार्ग दर्शन के परिणाम स्वरूपमध्यप्रदेश में जल जीवन मिशन से बुरहानपुर हर घर जल सर्टिफाइड जिला घोषित हो चुका है। इस श्रेणी में बुरहानपुर को देश में पहला जिला होने का गौरव हासिल हुआ है। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को क्रियाशील घरेलू नल कनेक्शन द्वारा शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाना लक्षित किया गया है। प्रदेश में भी एक करोड़ 22 लाख से अधिक ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन से हर घर जल का लक्ष्य रखा गया है। प्रदेश में मिशन के अंतर्गत विधिवत कार्य मई 2020 में प्रारंभ किए गए थे। कोविड-19 के प्रभाव और दो वर्षाकाल के बावजूद भी मिशन में तीव्र गति से हो रहे कार्यो के चलते ग्रामीण आबादी को नल से जल उपलब्ध करवाने की ओर मध्यप्रदेश अग्रसर है। अब बुरहानपुर जिले के समस्त 254 ग्रामों के परिवार प्रतिदिन अपने घर में नल कनेक्शन से जल प्राप्त कर रहे हैं।

जल जीवन मिशन में इस वर्ष ग्रामीण क्षेत्रों में एकल तथा समूह जल-प्रदाय योजनाओं से 20 लाख से अधिक क्रियाशील घरेलू नल कनेक्शन लगाये जाने

का लक्ष्य है। मध्यप्रदेश की 43 प्रतिशत से अधिक ग्रामीण आबादी अब जल जीवन मिशन से लाभान्वित होकर घर पर ही नल से जल प्राप्त कर रही है। मिशन में 51 लाख 81 हजार से अधिक ग्रामीण परिवारों को नल से जल मुहैया कराया जा चुका है। संकल्प पूर्ति की ओर यह निरन्तर बढ़ते कदम है। अब तक प्रदेश के 5521 गाँवों में शत प्रतिशत परिवारों को हर घर जल उपलब्ध हो रहा है।

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षित एवं निर्धारित मात्रा में शासन की नीति एवं निर्देशों के अनुरूप पेयजल प्रदाय हेतु नल-जल योजनाओं का सर्वेक्षण, अन्वेषण, हैंडपंप स्थापना एवं उनके संधारण, पेयजल गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्रों में शुद्ध एवं सुरक्षित पेयजल प्रदाय हेतु पेयजल स्त्रोतों की जल गुणवत्ता की निगरानी एवं अनुश्रवण सहित सहायक गतिविधियों का क्रियान्वयन निरंतर कर रहा है। पेयजल स्त्रोतों का प्रारंभिक गुणवत्ता परीक्षण पंचायत स्तर पर ही किया जाता है। पंचायत स्तर पर चयनित स्थानीय व्यक्तियों को विभाग द्वारा प्रशिक्षण दिया गया है। जल गुणवत्ता परीक्षण के लिये प्रदेश में भोपाल मुख्यालय पर राज्य अनुसंधान प्रयोगशाला तथा 51 जिलों में जिला पेयजल परीक्षण प्रयोगशाला और अतिरिक्त 103 उपखण्ड स्तरीय प्रयोगशालाएँ स्थापित हैं।

मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित द्वारा सतही स्त्रोत पर आधारित समूह जल-प्रदाय योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। जल निगम प्रत्येक ग्रामीण परिवार को क्रियाशील घरेलू नल कनेक्शन द्वारा गुणवत्तापूर्ण पेयजल की दीर्घकालिक उपलब्धता सुनिश्चित करना, उद्योगों को रॉ वाटर उपलब्ध कराना तथा तरल अपशिष्ट का सुरक्षित निष्पादन आदि कार्य किये जाते हैं। मध्यप्रदेश जल निगम द्वारा सतही स्त्रोत पर आधारित 25 समूह जल-प्रदाय योजनाओं के कार्य पूर्ण कर 995 ग्रामों में 2 लाख 2 हजार घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से पेयजल प्रदाय किया जा रहा है। वर्तमान में जल निगम के माध्यम से 14 हजार 248 करोड़ रूपये की 44 समूह जल- प्रदाय योजनाओं के कार्य प्रगतिरत है, जिनसे 19 लाख 17 हजार घरेलू नल कनेक्शन दिये जा सकेंगे। इसके अतिरिक्त 47 समूह जल-प्रदाय योजनाओं की निविदा/अनुमोदन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। इनके क्रियान्वयन से 15 हजार 463 ग्राम लाभान्वित होंगे।

लेखक राज्य मंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग मंत्री हैं

प्रदेश में बारिश, बाढ़ और बदइंतजामी

प्रदेश में बाढ़ बारिश का कहर...
चारों ओर मचा हाहाकार

विजया पाठक

अगस्त माह में पूरे देश के साथ मध्यप्रदेश में भी बारिश और बाढ़ ने कहर ढाया। चारों ओर बाढ़ और बारिश से हाहाकार मचा रहा। प्रदेश की सभी प्रमुख नदियों में जल सर बढ़ने से नदियों के किनारे बसे शहरों, कस्बों और गांवों में नदियों का पानी घुसा। हालात बेकाबू होते गए। जानमाल के साथ फसलों को भी काफी नुकसान पहुंचा। भीषण बाढ़ के बाद आज भी प्रदेश में हालात ठीक नहीं हो पाये हैं। खासकर चंबल नदी में आयी बाढ़ ने पूरे चंबल क्षेत्र को बर्बाद कर दिया। आज भी उस क्षेत्र में हालात बेहतर नहीं हो पाये हैं। अगस्त 2022 में अजब एमपी में गजब की बारिश हुई। ऐसी बारिश कि जनता त्राहिमाम कर रही थी। भोपाल की गलियों में सैलाब बह रहा था। क्या पॉश, क्या आम हर इलाका पानी पानी था। राहत टीम लगातार लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने का काम कर रही थी। भारी बारिश और बिगड़ते हालातों के बीच डैम के दरवाजे खोले जा रहे थे जिसने मुसीबत को और बढ़ा दिये। मध्यप्रदेश में आई बाढ़ के चलते हालात काफी खराब थे। सूबे में बाढ़

प्रदेश में बाढ़ के विकराल रूप से करीब 05 हज़ार मकान टूटे हैं और नदी के तेज़ बहाव में एक दर्जन पुल बह चुके हैं या क्षतिग्रस्त हुए हैं।

और उससे जुड़ी घटनाओं में दर्जनों लोगों की मौत हुई। वहीं, बाढ़ से लगभग 1250 गांव प्रभावित हुए। भारी बारिश से ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, श्योपुर, दतिया, अशोकनगर, भिंड, रायसेन, भोपाल, होशंगाबाद और मुरैना में काफी नुकसान हुआ। बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने में NDRF वायुसेना और सेना जुटी रही। हजारों लोगों को रेस्क्यू किया गया। सूबे में बाढ़ के खतरे को देखते हुए करीब एक लाख लोगों को पहले ही सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया था। प्रदेश में बाढ़ के विकराल रूप से करीब 05 हज़ार मकान टूटे हैं और नदी के तेज़ बहाव में एक दर्जन पुल बह चुके हैं या क्षतिग्रस्त हुए हैं। भारी बारिश और डैम से छोड़े गए पानी की वजह से हालात बेकाबू हो गए थे। बाढ़ के कारण मकान क्षतिग्रस्त हो गए और फसलें नष्ट हो गईं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान स्वयं बाढ़ प्रभावित लोगों तक पहुंचे और लोगों

को सुरक्षित सानों तक पहुंचाने में मदद की। मुख्यमंत्री चौहान ने हवाई सर्वेक्षण भी किया है और विदिशा, गुना, सागर, राजगढ़ और भोपाल में बाढ़ वाले कई क्षेत्रों का दौरा किया है।

आपको बता दें कि मध्यप्रदेश में लगातार हो रही बारिश से हालात बिगड़ गए थे। 27 जिलों में हाल बेहाल थे, जन-जीवन ठहर सा गया था। लगातार बारिश से नर्मदा, चंबल, सुखतवा, हिरन, शेर, बेतवा, सोन, ताप्ती और शिप्रा समेत तमाम छोटी बड़ी नदियां उफान पर थी। आलम ये था कि सड़कों पर पानी भरा था, पुल-पुलिया

मध्यप्रदेश में लगातार हो रही बारिश से हालात बिगड़ गए थे। 27 जिलों में हाल बेहाल थे, जन-जीवन ठहर सा गया था। लगातार बारिश से नर्मदा, चंबल, सुखतवा, हिरन, शेर, बेतवा, सोन, ताप्ती और शिप्रा समेत तमाम छोटी बड़ी नदियां उफान पर थी।

डूब गईं थी। सैकड़ों कॉलोनियां जलमग्न थी। भोपाल में तो बारिश ने 6 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। कलियासोत डैम के 07 और भदभदा के 05 और केरवा डैम के 05 गेट खोलने पड़े। प्रदेश में दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा बारिश गुना में हुई। नर्मदापुरम में सुखतवा नदी के पुल पर पानी आने से भोपाल-नागपुर नेशनल हाईवे बंद हो गया।

शांति का टापू कहा जाने वाला मध्यप्रदेश इन दिनों पूरी तरह से जलमग्न हो गया था। एक तरफ जहां प्रकृति ने प्रदेश के लोगों पर कहर बरपाया वहीं, दूसरी ओर प्रदेश सरकार के सुस्त मंत्रियों और उनके

नर्मदा नदी में बाढ़ से हाहाकार

प्रदेश की सबसे प्रमुख नदी नर्मदा ने भी अपना रौद्र रूप दिखाया। नदी के नजदीक शहरों और गांवों में नदी का पानी घुस जाने से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। हालात ऐसे थे कि कई शहरों से संपर्क टूट गया। तवा डैम से लगातार पानी छोड़े जाने से नर्मदा का जल स्तर लगातार बढ़ता गया। इसके अलावा नर्मदा की कई सहायक नदियों का पानी भी नर्मदा में मिला जिससे निचले हिस्सों में पानी भरा। महेश्वर घाट क्षेत्र के मंदिर में आधे से ज्यादा तक पानी चढ़ गया। बरसात में दूसरी बार महेश्वर किला गेट बंद किया गया।

विभाग के उदासीन रवैये का खामियाजा प्रदेश की जनता को भुगतना पड़ा। दरअसल पिछले दिनों राजधानी भोपाल सहित समूचे प्रदेश के विभिन्न जिलों में भारी बारिश हुई। लगातार हुई बारिश के कारण भोपाल के कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बनी तो अन्य जिलों के ग्रामीण क्षेत्र बुरी तरह से बाढ़ की चपेट में आये। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि आखिर हर साल बारिश में होने वाले जलभराव को रोकने के लिए करोड़ों रुपये का बजट पास किया जाता है। फिर यह बजट खर्च कहां होता है। क्यों सरकार के नुमाइंदे जलभराव से बचने के लिए बेहतर व्यवस्था करते हैं। इस बार भी यही हुआ सिर्फ राजधानी भोपाल में ही नगर निगम के अधिकारियों ने सीवेज सफाई और जलभराव की समस्या को दूर करने के नाम पर एक हजार करोड़ रुपये से अधिक चटकार लिये। जब प्रदेश की राजधानी भोपाल का यह आलम है तो फिर सोचने वाली बात है कि अन्य जिलों का क्या हाल होगा।

इसके साथ ही मध्यप्रदेश के विभिन्न जिलों में पिछले दिनों भारी बारिश के बाद प्रदेश के बदइंतजामी की पोल खुल गई। नदियां उफान पर थी, बांधों के कई पाटों को खोल देना पड़ा और भारी बारिश की चेतावनी देते हुए प्रदेश के कई इलाकों में रेड अलर्ट जारी करना पड़ा। बारिश ने लोगों का जीवन दूभर कर दिया। मप्र की राजधानी भोपाल की ही बात की जाए तो 24 घंटों में 10 इंच बारिश दर्ज की गई और हालात इतने खराब हो गए हैं कि घंटों

बिजली बंद रही और लोगों का आवश्यक वस्तुओं को खरीदने घर से जाना भी मुश्किल हो गया है। स्कूल-कॉलेजों में अवकाश घोषित करना पड़ा। यदि खबरों पर सरसरी निगाह भी डाली जाए तो मंजर भयावह हो चुका था क्योंकि बारिश से गांव के गांव तबाह हुए हैं और लोगों को विस्थापित होना पड़ा है। उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया।

यह बात बार-बार दोहराई जाना चाहिए कि हर साल बाढ़ आती है और इससे होने वाली बर्बादी का अंदाजा लगाया जाता रहा है लेकिन इससे निपटने की कोई योजनाबद्ध, सुविचारित रणनीति के अभाव में यह बर्बादी कई गुना भयावह हो जाती है।

चंबल नदी का कहर

ऊपरी क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश और कोटा बैराज से निरंतर छोड़े जा रहे पानी की वजह से चंबल नदी रौद्र रूप में आ गई। चंबल नदी के राजघाट पर जल स्तर 144 मीटर पहुंचने की वजह से जहां पुराना पुल पूरी तरह से डूब गया। वहीं संबलगढ़ से लेकर पोरसा तक के करीब एक सैकड़ा गांवों में पानी घुस गया। कई गांवों से हजारों ग्रामीणों को रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया। बाढ़ का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मुरैना आए और उन्होंने अंबाह तहसील के बीरपुर व कुठियाना गांव में पहुंचकर बाढ़ की विभीषिका का जायजा लिया। आपको बता दें कि कोटा बैराज से 04 लाख 87,000 क्यूसेक पानी प्रति सेकेंड चंबल नदी में डिस्चार्ज किया जा रहा था। चंबल नदी में पानी छोड़े जाने की वजह से हालात खराब हुए। भिण्ड के भी काफी गांवों में बाढ़ का पानी घुसा।

विदिशा जिले में 37 वर्षों बाद बाढ़ ने बिगाड़े हालात, 53 गांव टापू बने

जिले में 36 घंटों की वर्षा ने 37 वर्षों के बाद बाढ़ के हालात बना दिए थे। इसके पहले वर्ष 1885 में बाढ़ के इतने भयावह हालात बने थे। इस बाढ़ से जिले के करीब सौ गांव डूब में आ गए, इनमें से 53 गांव चारों तरफ से पानी से घिरने के कारण टापू बन गए। 14 गांवों में स्थिति ज्यादा खराब थी। सारे नदी–नाले उफान पर होने के कारण तहसील मुख्यालयों का जिला मुख्यालय से सड़क संपर्क टूट गया था। कलियासोत और भदभदा बांध के गेट खुलने के कारण बेतवा नदी ने खतरे का निशान पार कर लिया था। बेतवा के बढ़ते जल स्तर को देखते हुए जिला प्रशासन ने नदी किनारे के गांवों को खाली करा लिया था। इन गांवों के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। जिले में करीब एक दर्जन गांव बाढ़ के पानी से चारों ओर से घिर गए थे। यह पहला मौका था जब जिले में एक सप्ताह के भीतर दूसरी बार बाढ़ के हालात बन गए। इससे पहले भी जिले में आई बाढ़ से 19 गांव प्रभावित हुए थे।

कहने की जरूरत नहीं कि इसकी खामियाजा आम लोगों को ज्यादा भुगतना पड़ता है। विस्थापन के कारण लोगों को रोजी रोटी के लाल पड़ जाते हैं, उनका रोजगार छिन जाता है और जीवन पहले से ज्यादा कठिन होता जाता है। लाखों लोगों के बाढ़ में फंसे होने के कारण उन्हें होने वाली विकराल समस्या का सिर्फ अंदाजा ही लगाया जा सकता है। स्थानीय प्रशासन, स्वयंसेवी संगठनों और सेना की मदद से एक हद तक इस स्थिति से निपटने की कोशिश की जाती है लेकिन यह कहना होगा कि आपात स्थिति से निपटने के लिए जो समुचित तैयारी होना चाहिए उसका हर जगह सर्वथा अभाव देखा और महसूस किया जा सकता है। लेकिन भारी बारिश से होने वाली तात्कालिक समस्या से तो एक हद तक जैसे तैसे निपट लिया जाता है लेकिन बाढ़ की भयावह स्थिति के कारण खेतों और उर्वर जमीन के लिए दीर्घकालीन दृष्टि से भयावह साबित होता है क्योंकि बाढ़

से न केवल लाखों हैक्टेयर खेत बर्बाब हो जाते हैं बल्कि इसकी उर्वर मिट्टी भी बह कर चली जाती है और इससे किसानों को ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। यह कहने की जरूरत नहीं कि किसान किस तरह से कर्जा लेकर कठिन स्थितियों में खेती करता है और उस पर आसमान से बरसता कहर उसे और मुश्किल स्थितियों में डाल देता है। कहने की जरूरत नहीं कि देश की अर्थव्यवस्था में खेती का योगदान बहुत बड़ा है। कहने की जरूरत नहीं कि भारी बारिश और बाढ़ से देश की अर्थव्यवस्था पर कितना प्रतिकूल असर डालती है।

बाढ़ और अतिवृष्टि से जूझते लोगों की समस्या का निदान जरूरी

समूचा आज विकास की ऐसी चादर ओढ़े हुए है कि वह इस बात से पूरी तरह से अनभिज्ञ है कि अगर देश में पर्यावरण संरक्षण नहीं हुआ तो आने वाला समय कितना भयानक होगा। कुछ दिनों की बारिश में जब देश के कई राज्यों में जलभराव की स्थिति बन जाती है तो जरा सोचिए कि जब हर जगह निर्माण कार्य हो जायेंगे और कहीं भी ड्रेनेज सिस्टम ठीक नहीं होगा तो क्या स्थिति उत्पन्न होगी। यह सोचकर भी मन घबराता है। क्योंकि पिछले दिनों मध्यप्रदेश ने जो बारिश का दौर देखा है उसे देखने के बाद यह लगने लगा है कि प्रदेश सहित समूचे देश में बेहतर ड्रेनेज सिस्टम और पानी की निकासी को लेकर प्लानिंग के तहत कार्य करने की आवश्यकता है। सिर्फ डिजास्टर मैंनेजमेंट के भरोसे चीजों को नहीं छोड़ा जा सकता। इसे लेकर प्री प्लानिंग जरूरी है, तभी हम आमजन और मुख्य रूप से ग्रामीण परिवेश की आबादी को सुविधा दे सकते हैं। अतिवृष्टि और बाढ़ प्रबंधन की तैयारियाँ पूरी तरह से करें। इसके साथ ही बाँधों में

बाढ़ से न केवल लाखों हैक्टेयर खेत बर्बाब हो जाते हैं बल्कि इसकी उर्वर मिट्टी भी बह कर चली जाती है और इससे किसानों को ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता है।

शिवराज सरकार के दो मंत्रियों तुलसी सिलावट और भूपेन्द्र सिंह का आउटपुट शून्य

प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रदेश में आई बाढ़ का जायजा लेने के लिए पहले हैलीकॉप्टर और फिर मैदानी स्तर पर जाकर लोगों से मिले और उन्हें ढांढस बंधाने का प्रयास किया। लेकिन जिन विभागों के मंत्रियों के पास बाढ़ की समस्या को दूर करने और लोगों को परेशानी से बचाने का जिम्मा था वे मंत्री न तो बंगले से बाहर निकले और न ही अपने क्षेत्र में आई बाढ़ की इस विपदा से लोगों को बाहर निकालने के बारे में सोचा। जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट जिनके पास प्रदेश के बांधों के संरक्षण का जिम्मा है। वे पिछले ढ़ाई सालों से महज भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का कार्य कर रहे हैं। धार जिले का कारम बांध भ्रष्टाचार का ही एक बड़ा उदाहरण है। मंत्री सिलावट की लापरवाही के कारण 16 गांव के लोगों को अपना ठिकाना छोड़ राहत शिविर की शरण लेना पड़ा। यही नहीं नगरीय निकायों में लोगों को जलभराव की स्थिति से बचाये रखने की जिम्मेदारी प्रदेश के नगरीय निकाय मंत्री भूपेंद्र सिंह की है। लेकिन भूपेन्द्र सिंह पूरी तरह से सत्ता मोह में इस तरह से लिप्त है कि उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि प्रदेश में क्या घट रहा है। कुल मिलाकर शिवराज सरकार के दोनों मंत्रियों का आउटपुट शून्य है।

ऐसे मंत्रियों को कैबिनेट से बाहर कर देना चाहिए- जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट और नगरीय निकाय मंत्री भूपेंद्र सिंह के कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड देखे तो सिवाय भ्रष्टाचार के कुछ नहीं मिलेगा। दोनों ने ही अपने विभागों में टेंडर, ट्रांसफर, पोस्टिंग तक में धांधली मचा रखी है। जिसका नतीजा है कि प्रदेश की जनता गांवों में और शहरों में छोटी-छोटी चीजों को लेकर परेशान हो रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को तुरंत इस तरह के नाकामयाब मंत्रियों को कैबिनेट से बाहर का रास्ता दिखा देना चाहिए। क्योंकि आज यदि मध्यप्रदेश जलमग्न हुआ है तो केवल इन दोनों मंत्रियों की वजह से।

वर्षा जल के अधिक भराव को नहरों में छोड़कर फसल उगाने वाले किसानों के खेतों तक भी पानी पहुँचाना व्यर्थ पानी बहाने का अच्छा विकल्प हो सकता है। वर्षा जल संरक्षण पर वन, ग्रामीण विकास, जल-संसाधन विभाग समन्वित कार्य-

53 गांव बाढ़ के पानी से टापू बने- जिले में लगातार वर्षा के कारण सौ गांव प्रभावित हुए, इनमें 53 गांव चारों तरफ से पानी से घिरने के कारण टापू में तब्दील हो गए थे। 14 गांवों पूर्ण रूप से डूब में आ गए थे। नटेरन तहसील अन्तर्गत 14 ग्राम, कुरवाई में 22, शमशाबाद में 16, गुलाबगंज में 01, त्यौंदा में 06, सिरोंज में 01, बासौदा में 05 एवं विदिशा ग्रामीण के 33 ग्राम बाढ़ की चपेट में थे।

शहर की निचली बस्तियों में भरा पानी- विदिशा शहर में इस बार निचली बस्तियों में पानी घुस गया। इसके अलावा शहर की कई सड़कें पानी में डूबी रही, जिसके कारण कई क्षेत्रों के सीधे रास्ते बंद हो गए।

देवास में भी बुरे हैं हालात- देवास जिले के ऊपरी क्षेत्रों में हो रही लगातार बारिश और अन्य जिलों की बारिश के बाद देवास जिले के नेमावर में नर्मदा नदी का जलस्तर बीती रात से बढ़ने लगा था। नर्मदा से लगी कुछ सहायक नदियों के जलस्तर में भी लगातार बढ़ोतरी हुई। नर्मदा का जलस्तर 889 फीट पर पहुंचा। यानी की खतरे के निशान से 04 फीट ऊपर। कई गांवों में बाढ़ जैसे हालत बने।

भोपाल में खोले गये बांधों के फाटक- भोपाल के केरवा के आठ के आठ, कलियासोत के 13, विदिशा के 10, अशोकनगर के राजघाट के 18 में से 16 गेट खोले गए। जबकि नर्मदा बेसिन के बरगी डैम के 21 में से 17, बरना डैम के छह, तवा डैम के 13, इंदिरा सागर बांध के 12 और ओमकारेश्वर डैम के 18 गेट खोले गए थे। भारी बारिश के चलते राज्य के 50 डैम ओवरफ्लो हो गए थे।

आगर मालवा जिले में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त- आगर मालवा जिले में लगातार बारिश से जन जीवन अस ुच्च हो गया था। बढ़ते जलस्तर के चलते जिले की सीमा

योजना बनायें। कार्य-योजना ऐसी हो, जिसमें अतिवृष्टि से बाढ़ से बचाव के साथ-साथ वर्षा जल का उपयोग और संरक्षण भी किया जा सके। वर्षा जल संरक्षण महत्वपूर्ण कार्य है।

प्राकृतिक विपदाओं पर तेज प्रतिया के लिए सम्यक योजना और उसे लागू करने वाला ढांचा जरूरी है। त्वरित राहत के अतिरिक्त पुनर्वास का काम सुदृढ़ और

पर बने क्षेत्र के सबसे बड़े कुंडालिया डैम के 09 गेट को खोलना पड़ा। बांध से बड़ी मात्रा में पानी की निकासी की गई। बांध से पानी छोड़े जाने से काली सिंध नदी का जलस्तर बढ़ गया था। बारिश के चलते जिले की लखुंदर, कालीसिंध, कंठाल सहित सभी नदी नाले उफान पर थी।

राजगढ़ और मंदसौर में हालात हुए बेकाबू- जिलों में हुई लगातार बारिश के कारण राजगढ़ और मंदसौर में हालात बेकाबू रहे। राजगढ़ के डैम मोहनपुरा, कुशलपुरा और कुंडालिया और छोटे डैम के गेट खोलकर पानी छोड़ा गया जिससे जिले के अधिकांश हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात बने। वहीं मंदसौर में 24 घंटे में तकरीबन 04 इंच बारिश हुई जिससे जनजीवन को प्रभावित हुआ। शिवना नदी उफान पर हुई। शिवना नदी के किनारे गांव के लोगों को ऊंची जगहों पर पहुंचाया गया।

गुना में 20 घंटे टापू पर फंसे रहे 03 ग्रामीण- गुना में हुई बारिश के कारण बमोरी इलाके के पीपल्या गांव में भैंस चराने गए 3 ग्रामीण टापू पर फंस गए। 20 घंटों तक वह टापू पर फंसे रहे। प्रशासन ने उन्हें एयरलिफ्ट करने के लिए गृह विभाग को मदद के लिए पत्र भी भेज दिया था। अगले दिन जब सुबह पानी थोड़ा कम हुआ तो एसडीआरएफ की टीम ने अपनी बोट उतार उनका रेस्क्यू किया।

नर्मदापुरम में भोपाल-नागपुर नेशनल हाईवे पर आवागमन बंद- नर्मदापुरम में बारिश से हालत बेकाबू थे।

पारदर्शी होना चाहिए और नुकसान को कम से कम करने की सूक्ष्म कार्ययोजना तैयार रहनी चाहिए। दीर्घ अवधि के उपाय भी महत्वपूर्ण हैं। जंगल न काटे जाएं, सड़क निर्माण में प्राकृतिक संतुलन का ख्याल रखा जाए, शहरीकरण को पर्यावरणीय संतुलन के साथ चलाया जाए, कार्बन उत्सर्जन रोकने के लिए उद्योगों, बिजली संयत्रों, रिफाइनरियों, और कार्बन उत्सर्जित

सुखतवा में नदी के पुल पर पानी आने से भोपाल-नागपुर नेशनल हाईवे पर आवागमन बंद की स्थिति कायम हुई। दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार थी। पिपरिया के लोगों को 24 घंटे तक अंधेरे में रहना पड़ा।

सागर में भरभराकर गिरा मकान- सागर में सबसे ज्यादा बारिश जैसीनगर में हुई। सिंगारचोरी, बांसा समेत अन्य आसपास के गांवों के रास्तों में बंद की स्थिति पैदा हुई। बीना नदी और रहली से निकली सुनार नदी में जलस्तर बढ़ा।

जबलपुर में बरगी डैम के 17 गेट खुलने से नर्मदा रौद्र रूप में- जबलपुर में हुई भारी बारिश के बाद रांझी बिलहरी सहित अनेक स्थानों में दर्जनों पेड़ भी टूट गए थे। बरगी डैम के 17 गेट खुलने से नर्मदा रौद्र रूप में आ गई थी। ग्वारीघाट में बनी दुकानें डूब गई थी। करमचंद चौक के पास एक जर्जर मकान गिर गया। घर में फंसे 07 लोगों को निकाला गया।

नरसिंहपुर में झांसी घाट पुल डूबा, तेंदूखेड़ा- गाडरवारा मार्ग बंद- नरसिंहपुर जिले में लगातार हुई बारिश के चलते नर्मदा नदी सहित सभी नदी-नाले उफान पर थे। नर्मदा का झांसी घाट का पुल डूबने से जबलपुर-नरसिंहपुर मार्ग बाधित हुआ।

दमोह के सुनार नदी पर बना पुल डूबा- दमोह में दमोह-पथरिया मार्ग पर सुनार नदी पर बना पुल डूब गया। आवागमन बंद हो गया। लोग रेलवे पुल से आने को मजबूर थे। नदी किनारे के करीब आधा दर्जन से अधिक गांवों के कुछ घरों में पानी भर गया।

राज्यसेन में बिजली गुल, कलेक्टर के बंगले में घुसा पानी- रायसेन जिले में नदी-तालाब उफान पर थे। चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा था। शहर सहित जिले भर में हो रही मूसलाधार बारिश से रास्ते बाधित हुए। रायसेन में हालात यह थे कि निचली बस्तियों सहित कलेक्टर का बंगला, तहसील, एसडीएम कार्यालय में पानी भर गया। शहर के मुख्य बाजार, नगर पालिका भवन के सामने लगभग तीन फीट पानी तक पानी था। कई दुकानों में भी पानी भर गया था। मूसलाधार बारिश के साथ चली आंधी से शहर में कई पेड़ धराशाई हो गए। इससे बिजली के तार भी टूट गए जिसके कारण जिले में बिजली पूरी तरह से गुल हो गई थी।

करने वाले अन्य उपमों, उद्यमों को लेकर एक नीति बने। नागरिक भागीदारी बढ़ाई जाए। वृक्षारोपण को एक दिन का नारा बनाने के बजाय एक ठोस लक्ष्य बनाया जाए। कानून कड़े और सजाओं का प्रावधान हो। भूजल संग्रहण के साथ-साथ पानी की बर्बादी रोकने के उपाय भी किए जाने चाहिए। वाहनों की आमद और प्रदूषण के लिए बाध्यकारी उपाय चाहिए।

पब्लिक ट्रांसपोर्ट की दशा सुधारनी होगी। सार्वजनिक सेवाओं का इतना निजीकरण एक बेकाबू फिसलन है। जलवायु परिवर्तन और तापमान वृद्धि के रूप में, प्रकृति अपनी अतिशयता और कोप दिखा रही है।

भारत में घटित होने वाली सभी प्राकृतिक आपदाओं में सबसे अधिक घटनाएँ बाढ़ की हैं। इसका मुख्य कारण भारतीय मानसून की अनिश्चितता तथा वर्षा ऋतु के चार महीनों में भारी जलप्रवाह है, परंतु भारत की असम्मित भू-आकृतिक विशेषताएँ विभिन्न क्षेत्रों में बाढ़ की प्रकृति तथा तीव्रता के निर्धारण में अहम भूमिका निभाती हैं। बाढ़ के कारण समाज का सबसे गरीब तबका प्रभावित होता है। बाढ़ जान-माल की क्षति के साथ-साथ प्रकृति को भी हानि पहुँचती है। अतः सतत् विकास के नज़रिये से बाढ़ के आकलन की ज़रूरत है। सामान्यतः भारी वर्षा के बाद जब प्राकृतिक जल संग्रहण स्रोतोंमार्गो की जल धारण करने की क्षमता का संपूर्ण दोहन हो जाता

भारत में घटित होने वाली सभी प्राकृतिक आपदाओं में सबसे अधिक घटनाएँ बाढ़ की हैं। इसका मुख्य कारण भारतीय मानसून की अनिश्चितता तथा वर्षा ऋतु के चार महीनों में भारी जलप्रवाह है, परंतु भारत की असम्मित भू-आकृतिक विशेषताएँ विभिन्न क्षेत्रों में बाढ़ की प्रकृति तथा तीव्रता के निर्धारण में अहम भूमिका निभाती हैं। बाढ़ के कारण समाज का सबसे गरीब तबका प्रभावित होता है।

है, तो पानी उन स्रोतों से निकलकर आस-पास की सूखी भूमि को डूबा देता है लेकिन बाढ़ हमेशा भारी बारिश के कारण नहीं आती है, बल्कि यह प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों ही कारणों का परिणाम है। बाढ़ का पानी संमण को अपने साथ लाता है बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में कई तरह की बीमारियाँ, जैसे- हैजा, आंत्रशोथ, हेपेटाईटिस एवं अन्य दूषित जलजनित बीमारियाँ फैल जाती हैं। बाढ़ की स्थिति इसे और अधिक हानिकारक बना सकती है। असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश (मैदानी क्षेत्र) और ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और गुजरात के तटीय क्षेत्र तथा पंजाब, राजस्थान, उत्तर गुजरात एवं हरियाणा में बार-बार बाढ़ आने और कृषि भूमि तथा मानव बस्तियों के डूबने से देश की अर्थव्यवस्था तथा समाज पर गहरा प्रभाव पड़ता है। मध्यप्रदेश के धार में कारम डैम में हमने गंभीर हालातों को देखा। देश में असम में बाढ़ हो या हिमाचल में अतिवृष्टि हर जगह सरकारी प्रबंधन बौने नजर आते हैं। बाढ़ से बचने के लिए इस बारे में गंभीरता से सोचना जरूरी है, बारिश पूर्व और अतिवृष्टि के क्षेत्रों में शासन-प्रशासन को अधिक मुस्तैदी से आंकलन कराने की जरूरत है।

Extreme Poverty and The Applications of Microfinance

Dravya Jain is an academically proficient high school student in California's Silicon Valley, consistently ranking in the top 9% in her grade. Apart from her busy coursework, she enjoys exchanging handwritten letters with friends from around the world. After one such exchange, Dravya realized the plight of those who are financially underserved by Ghana's government, and has decided to research the effects of microfinance industries in developing countries.

Dravya Jain

Before beginning to understand how microfinance can address poverty, it is vital to have a clear definition of poverty itself. Poverty can be defined as a "situation where consumption falls short of the poverty line ($1 per day) as someone living below $1 daily income would be deprived of basic human needs such as food, safe drinking water, sanitation facilities, health, shelter, education, and information, etc. It is worthy of note that the number of people living below $1 per day expressed as a ratio of the total population is an indicator of the poverty rate in a country (Onyele et al)." This definition is supported: "When a person's income is below one dollar per day, that person is considered to be poor (Kim et al., 2017)." As a result of low income, poverty stricken individuals experience abominable conditions in basic practices, including food, shelter, hygiene, and health care. "Poverty means that basic needs like food, housing, lodging and clothes are deprived of life (G. O. Boateng et al., 2015; Shaikh, 2017). Poverty is a condition marked by a severe lack of basic human needs such as food, clean drinking water, hygiene, medical treatment, housing, employment etc. (Agbola et al., 2017)." Persons in poverty do not only have unacceptable forms of but also may not have at all basic life necessities such as "money, clothes, shelter, assets," and therefore are "characterized by hunger, social exclusion, vulnerability, low-esteem, pain and discomfort (G. O. Boateng et al., 2015) (Gakpo et al. 6).

So far, poverty has been examined through its impacts on financial situations,

however, poverty affects an individual in ways far beyond finance. "Poverty is a major way of describing …degradation of human dignity… it leads to social exclusion, isolation, fear, anxiety, and bereavement" (Backwith, 2015). From this lens, poverty is not merely a financial deprivation, but also a social and emotional one. In the same way, extreme poverty is not merely a deprivation, but also a shared and inherited way of living. It dictates a person's attitude, familial relations, and self-worth. "Culture of poverty is a pattern of life, which people adopt as a community, and is passed from one generation to the next. People adopt a submissive attitude that makes that feel marginalized, helpless and inferior. Family life usually ends in divorce resulting in the abandonment of the children and their mother." (Ezeanyeji et al. 9). Poverty strips individuals of their innate behaviors, eliminating any natural desires to participate in communities and politics. "Such individuals do not engage in community life by participating in voluntary associations, self-help initiatives and politics" (Ezeanyeji et al. 9). Impoverished persons experience a "loss of self-confidence, self actualization, self-fulfillment, lack of good orientation and abandonment of cultural values and heritage to the extent that people are not proud of their cultural and racial identity (Commins, 2004; Jencks, 1992; Porter & Washington, 1979; Shah, 2016)." Ceasing to make an effort and resigning oneself to a failure contributes to an overall loss of morals; persons in poverty exhibit a "disregard for ethics and low intellectualism, and wide spread of selfishness among people (Abimuku, 2006)." The

financial and social defeat persons in poverty experience "makes people… incapacitated and deprives them the enjoyment of development and sustenance (Ezeanyeji et al. 6)".

The scourge of poverty is not limited to a select unfortunate, in fact, "Half of the population of the world is living on less than $5 Dollars per day (World Bank, 2018). Even more so, "Approximately 40% of the global population lives below the poverty line (World Bank, 2019)." Many efforts to reduce poverty flounder and end, leaving "population of people that are still living in extreme poverty globally is still unacceptably high" (Ezeanyeji et al. 2)." Although poverty is a global experience, it is concentrated primarily in developing countries. "The top five (5) countries with the highest number of people living in extreme poverty are: (in no particular order): Nigeria, Bangladesh, Democratic Republic of Congo, India, and Ethiopia (World Bank, 2018)" (Ezeanyeji et al. 2) Many other regions of the world endure severe poverty as well, including Sub-Saharan Africa, which is "the poorest region in the globe" (Ezeanyeji et al. 2), and the Philippines, where "approximately 16.5% of the society experienced poverty and 5.7% lived in extreme poverty in 2015" (Janiczak-Serafico 37).

Since such a startling percent of the world population lives in poverty; the reason for such tremendous numbers must be investigated. There are a multitude of factors causing and perpetuating poverty, most notably

including reasons relating to a weak financial infrastructures, lack of awareness, inadequacy of entrepreneurial skills, and a deficiency in terms of technological advancements and updates. "The poverty rate in these countries is high because they are characterized by low capital formation, weak financial system, under-utilization of and over-reliance on natural resources, lack of entrepreneurial skills and initiatives, technological backwardness, rural-urban inequality" (Ezeanyeji et al. 3). As previously determined, residents of developing countries are particular target of extreme poverty. A reason for this may be found in the fact that most people in developing countries cannot obtain significant access to financial services, thus limiting their opportunities and contributing to their poor financial state. "..mostresidents in developing countries, Nigeria inclusive, lack access to formal financial ervices, and are impoverished as a result." (Onyele et al). This theory is supported: "One of the factors attributed to the rising poverty rate in developing countries is the lack of finance (World Bank, 2008)." These reasons elucidate why people fall into poverty, but not why they remain entangled in it.

There are two main theories regarding the perpetuation of poverty: the "culture of poverty" and the "individual deficiency theory." The former proposes that many remain impoverished as there is a

"culture of poverty." In other words, living in inconsiderable conditions is considered the norm, and this sense of normalcy is created as a result of ubiquitous "weak governance, impunity, systemic failures, illiteracy, income inequality, unemployment and corruption" (Ezeanyeji et al. 9). Furthermore, the meager resources of impoverished people are further depleted by corrupt politicians, who, especially in Nigeria, tend to be "...selfish, greedy and corrupt" and "enrich themselves by looting the commonwealth of the nation" (Ezeanyeji et al. 9). Corruption in such developing countries is exceedingly overwhelming and entwined with its government, making it nearly impossible to eradicate and therefore perpetuating poverty. The "individual deficiency theory" offers a cynical view on the hardships of impoverished people; it attributes poverty to an individual's flaws, not to their surroundings. It believes that the poor fail to escape poverty due to their foolish decisions and lack of will to improve their condition. "The theory cast the poor as a moral hazard with claims that poverty persist because they are not doing enough or are engaging in activities that are counterproductive (Gwartney & McCaleb, 1985)." The theory claims that "failure to enroll in schools, laziness, indiscipline and engagement in crime and other social ills are personal

choices that could result in poverty for individuals (Ezeanyeji et al. 10)."

Although attempts have been made to address the problem of poverty, its scope is vast and complex. Proposed solutions such as "poverty reduction programmes and policies" have been issued and have shown hopeful efforts, but ultimately do not achieve their goal (Ezeanyeji et al. 9). Essentially, "notable progress has been witnessed on poverty reduction," but most attempts fail to make a significant impact on the seemingly insolvable torment that is poverty. However, some efforts prove fruitful. As previously established, financial illiteracy and lack of economic services are major proponents of poverty. Therefore, providing a substantial financial education and access to economic resources is a feasible method of reducing poverty. "It is believed that by rendering financial services to these unreached, unserved, and unbaked portions of the population, will enable them to unleash their potentials, develop their capacity, strengthen their human and physical capital, and engage in productive activities that would generate income for their livelihoods and the benefits of their families" (Ezeanyeji et al. 3). Financial inclusion of the impoverished would ultimately integrate them into society, allowing them to escape poverty and navigate their lives with economic stability.

An example of financial inclusion providing a pathway out of poverty can be found in the solution microfinance, "a developmental strategy that is used to increase financial inclusion by broadening financial services accessibility to all strata of the population" (Apere, 2016; Kasali, et al., 2015). In broad terms, microfinance is a financial system through which low-income peoples are allowed access to financial services by retail providers, including comprising savings, credit, payments, remittances, and insurance. These financial opportunities in turn allow low-income peoples to possibly endeavor in businesses or jobs to generate stable incomes, acquire assets, maintain consumption, and gain knowledge protecting them against risks they face in an already vulnerable financial market for the poor (Ezeanyeji et al. 5). Microfinance primarily targets to a section of the general population that has been "excluded from the formal financial sector over the years simply because of their income level, gender, location, level of financial education etc" (Emmanuel, et al., 2015). It is important to note that despite being denied a place in the general financial group, these 'excluded peoples' are the majority of a developing country's economy - allowing them to join the general financial sector through microfinance can boost the country's financial status and lift the lowest population out of poverty (Ezeanyeji et al. 3).

जगत पाठक पत्रकारिता संस्थान, भोपाल

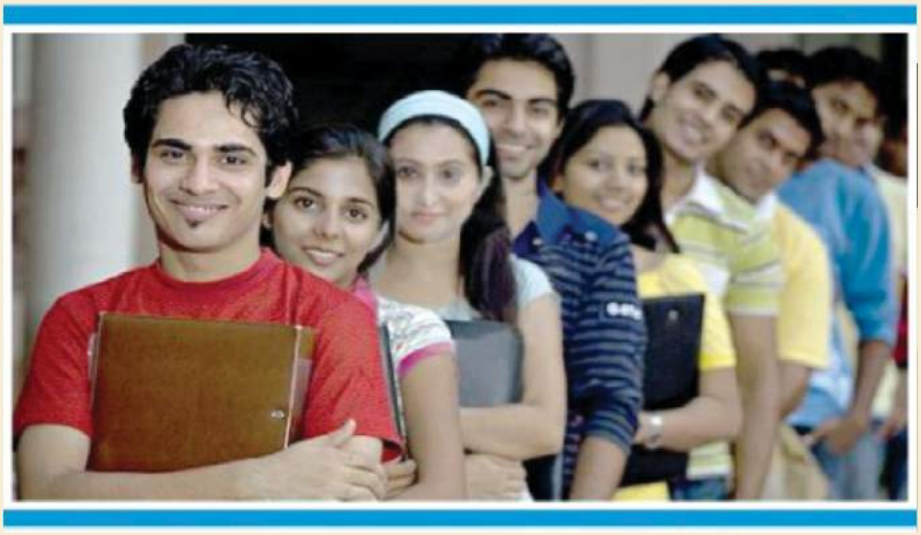

जगत पाठक पत्रकारिता संस्थान वर्ष 1998 से सतत् रूप से संचालित हो रहा है। इस संस्थान से अध्ययन कर छात्र-छात्राएं प्रिंट व इलैक्ट्रॉनिक मीडिया में अच्छे पदों पर पदस्थ हैं। साथ ही साथ शासकीय पद पर आसीन होकर इस संस्थान को गौरवान्वित कर रहे हैं।

: विषय :

मास्टर ऑफ आर्ट जर्नलिज्म (2 वर्ष)

प्रवेश प्रारंभ

संपर्क सूत्र

विजया पाठक (संचालक) - 9826064596

अर्चना शर्मा - 9754199671

कार्यालय - कार्पोरेट कार्यालय - एफ 116/17, शिवाजी नगर, भोपाल, म.प्र.

संस्थान - 28, सुरभि विहार कालोनी, कालीबाड़ी, बी.डी.ए. रोड, भेल, भोपाल, म.प्र.

SAWARNA COSMETICS

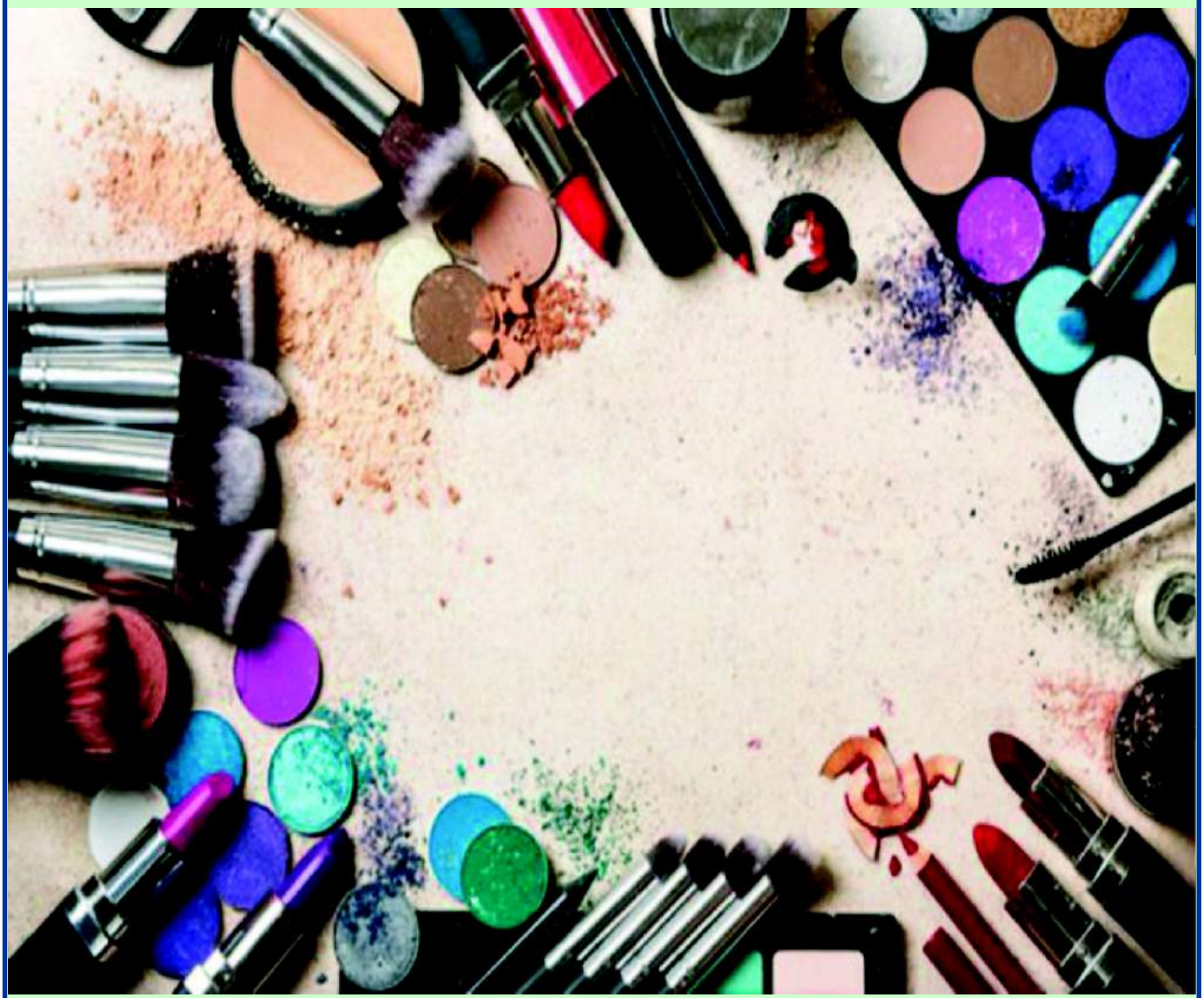

SHOP NO. 101/152, NEW MARKET,
BHOPAL, M.P. 462016

सावधानी से गाड़ी चलाएँ
या आप उसी जगह पँहुच जाएंगे
जहाँ जाना नहीं चाहते हैं।
जनहित के लिए जारी